NATION FIRST
POLICY RESEARCH CENTRE

एक्सप्लेनर

केन्द्रीय बजट

2026-27

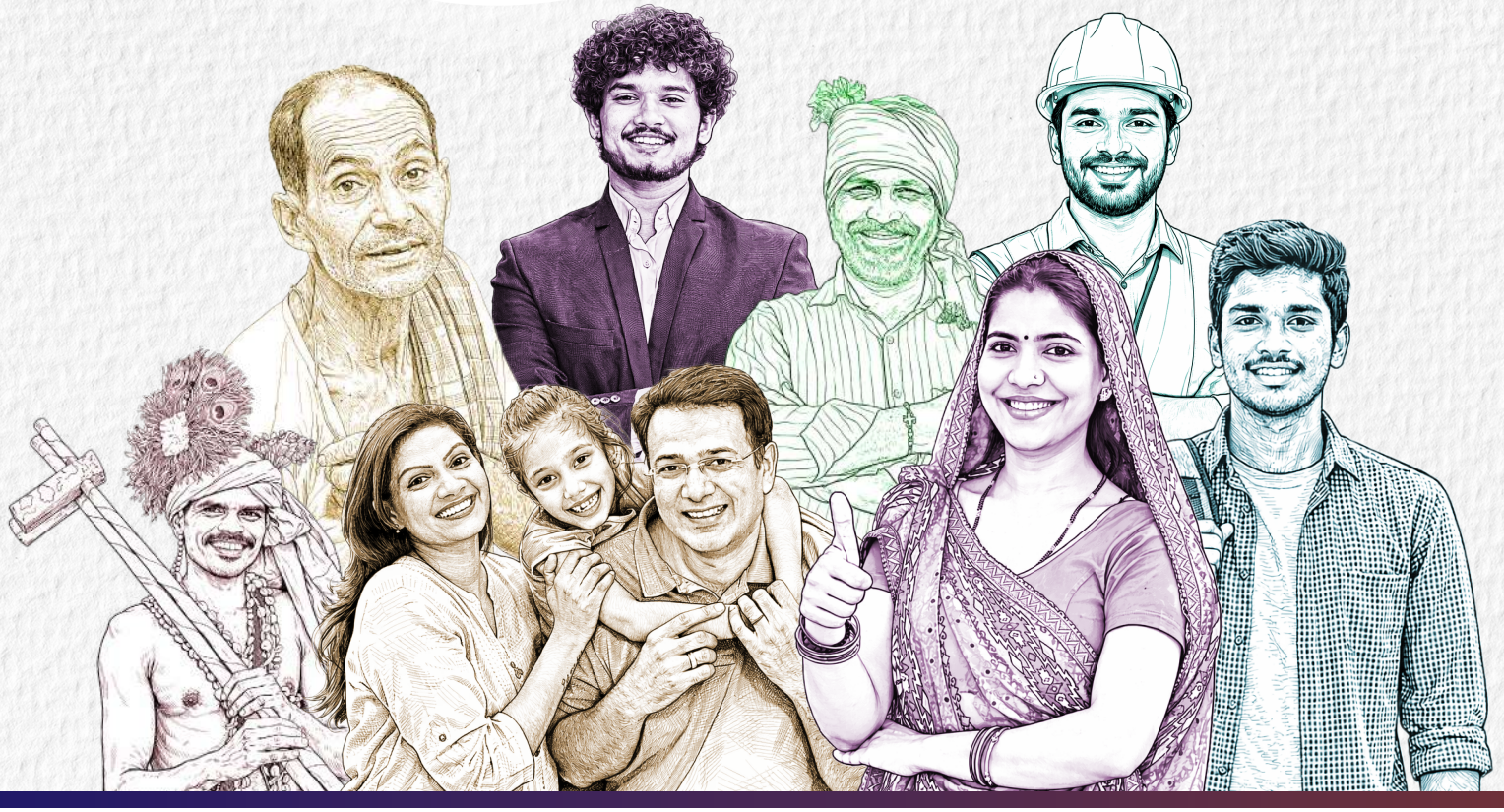

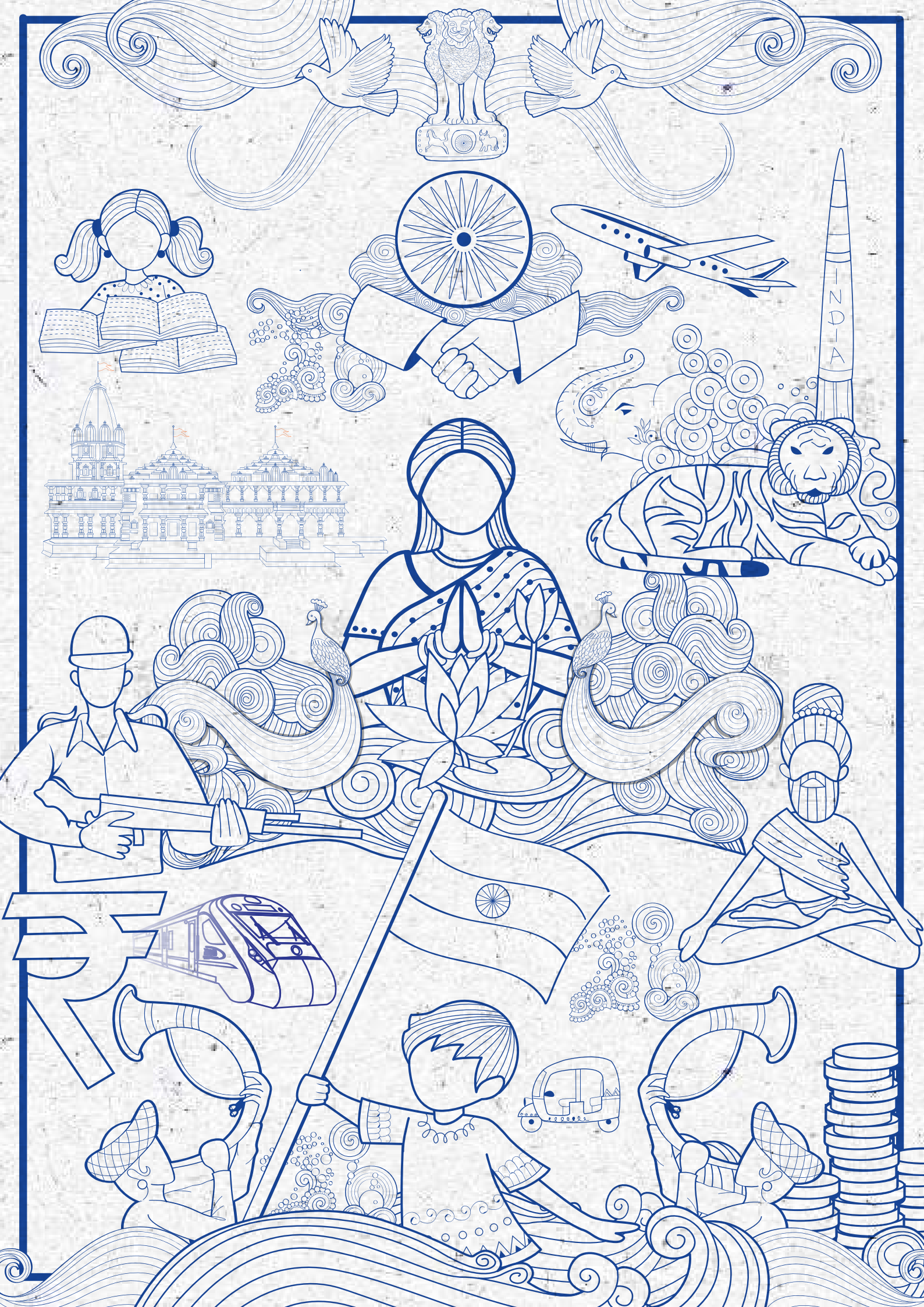
INDIA

विषय सूची

01 विकसित भारत के लिए सुधार 07

02 आधारभूत संरचना 27

03 वंचित वर्ग 43

04 मध्यम वर्ग 53

05 गरीब कल्याण 64

06 युवा 74

07 अन्नदाता 87

08 नारी 98

युवा शक्ति बजट–2026

तीन कर्तव्यों

पर आधारित है

- लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना
- आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना
- सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करना

विकसित भारत
के लिए सुधार

हाल के वर्षों में चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने सुधारों को एक **निरंतर राष्ट्रीय मिशन** के रूप में आगे बढ़ाया है। **विकास, स्थिरता और पारदर्शिता** पर निरंतर ध्यान से आर्थिक आधार मजबूत हुआ है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित हुई है।

विकसित भारत @2047 की परिकल्पना पर आधारित होकर, सरकार ने सुधारोन्मुखी कानूनों को आगे बढ़ाया है, **छोटे एवं तकनीकी अपराधों के अपराधीकरण को समाप्त किया** है, व्यवस्थित **विनियमन-उन्मूलन** किया है तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। श्रम और वित्तीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ विनिर्माण, निर्यात और **नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता** को प्रोत्साहन देकर, इन उपायों ने एक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार भारत की मजबूत नींव रखी है, जो **दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता** से सशक्त है।

- जीएसटी सुधार
- जन विश्वास
- बेहतर सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण
- वैश्विक व्यापार समझौते

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र-राज्य वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना

हस्तांतरण का ऊर्ध्वाधर हिस्सा:

- राज्यों को हस्तांतरण का हिस्सा **41%** पर बनाए रखना
- **वित्त वर्ष 2026-27** के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में **₹ 1.4 लाख करोड़** प्रदान किए गए
- अनुदान में **ग्रामीण और शहरी स्थानीय** निकाय अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं

प्रभाव

- वेतन, पेंशन और मुख्य योजनाओं के लिए राज्य के आधारभूत वित्त को सुरक्षित करता है
- मध्य-वर्ष के खर्च में कटौती को कम करता है

"चैंपियन एस.एम.ई" बनाना और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना

एस.एम.ई विकास कोष

- छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास पूंजी प्रदान करता है
- उन्हें परिचालन बढ़ाने, क्षमता का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद करता है
- कोष: **₹10,000 करोड़**

प्रभाव आशाजनक एस.एम.ई को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी फर्मों में बदलता है

आत्मनिर्भर भारत फंड की निरंतरता

- सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करता है और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखता है
- **₹ 1000 करोड़** का अतिरिक्त प्रावधा

प्रभाव सूक्ष्म उद्यमों को परिचालन बढ़ाने, औपचारिक बनाने और क्रेडिट झटकों (credit shocks) से बचने में मदद करता है

2025 को भारत के लिए उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब सुधारों को एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपनाया गया

नरेन्द्र मोदी

प्रतिस्पर्धी विकसित भारत के लिए पारदर्शी और सुगम कराधान

आयकर में जन विश्वास: छोटे अपराधों के लिए उदारता

- आयकर अधिनियम में **छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों** को अपराध की **श्रेणी से बाहर** करना
- कुछ मामलों में **1 अक्टूबर, 2024** से पूर्वव्यापी रूप से लागू
- केवल **गंभीर आर्थिक अपराधों** के लिए कड़ी सजा

प्रभाव

- व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देता है
- **विदेशी निवेशकों** में विश्वास सुधारता है

वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधार

- भारत में **डेटा सेंटरों** का उपयोग करने वाले विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को **2047** तक टैक्स हॉलिडे

प्रभाव

- **बड़े पैमाने पर निवेश** को प्रेरित करता है
- भारत को दुनिया का **डेटा सेंटर** हब बनाता है

अनिवासी कर सुधार

- अनिवासी विशेषज्ञों की **भारत के बाहर से प्राप्त आय को पांच साल के लिए कर से छूट दी जाएगी**
- अनुमानित आधार पर कर देने वाले अनिवासियों को **न्यूनतम वैकल्पिक कराधान (MAT) से छूट दी जाएगीAlternate Taxation (MAT)**

प्रभाव

- विशेष विदेशी **विशेषज्ञता को आकर्षित करने की भारत** की क्षमता में सुधार करता है

एम.ए.टी (MAT) क्रेडिट सेट-ऑफ नए टैक्स व्यवस्था से जुड़ा

- **लाए गए MAT क्रेडिट के सेट-ऑफ की अनुमति केवल नई व्यवस्था चुनने वाली कंपनियों के लिए है**
- नई कर व्यवस्था के तहत कर देयता के **1/4 तक सीमित**
- अंतिम कर और संबंधित दर को **15% से घटाकर 14% किया जाएगा**

प्रभाव

- अधिक **पारदर्शी और अनुमानित** व्यावसायिक वातावरण
- **सरल, कटौती-मुक्त कॉर्पोरेट कर प्रणाली** की ओर संक्रमण को तेज करता है
- सरल, कटौती-मुक्त कॉर्पोरेट कर प्रणाली की ओर संक्रमण को तेज़ करता है

विकास और निवेश में सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण

बैंकिंग सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति

- बैंकिंग क्षेत्र के नियमों की **व्यापक समीक्षा** करना
- वित्तीय स्थिरता, **समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित** करना

प्रभाव

बैंकिंग प्रणाली को तर्कसंगत बनाना और बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए **ऋण प्रवाह में सुधार करना**

विदेशी मुद्रा ढांचे की व्यापक समीक्षा

- **विदेशी निवेश** के लिए एक समकालीन, उपयोगकर्ता के **अनुकूल और निवेशक-संरेखित ढांचा लाना**
- 1970-80 के दशक की पूंजी नियंत्रण मानसिकता से हटकर फेमा **(FEMA) ढांचे का आधुनिकीकरण**

प्रभाव

- अनुपालन कम करके **पूंजी प्रवाह** में सुधार
- **विदेशी निवेशकों** को विश्वास प्रदान करता है

पूंजी बाजार सुधार

- धन और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए **मार्केट-मेकिंग ढांचा**
- कॉर्पोरेट बॉन्ड पर **टोटल रिटर्न स्वैप**

प्रभाव

- **कॉर्पोरेट्स के लिए पूंजी की लागत कम करता है**
- **खुदरा निवेशकों और म्यूचुअल फंड के लिए नए निवेश मार्ग**

नगर पालिका बॉन्ड बाजारों को मजबूत करना

- **₹1,000** करोड़ से अधिक के नगर पालिका बॉन्ड के लिए **₹100 करोड़ का** प्रोत्साहन
- अमृत (AMRUT) से जुड़े प्रोत्साहन **₹200** करोड़ तक के बॉन्ड के लिए जारी रहेंगे

प्रभाव

- बड़े नगर पालिका बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करता है
- शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी की लागत कम करता है
- शहरी स्थानीय निकायों के भीतर वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है

भारत में पूंजी केवल बढ़ती ही नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना

भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

- सेमीकंडक्टर विकसित करने के लिए नया ढांचा और कुशल कार्यबल
- उपकरण और सामग्री का उत्पादन
- फुल-स्टैक भारतीय आईपी (IP) डिजाइन करना
- घरेलू कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला बनाना

प्रभाव

- सेमीकंडक्टर आरएंडडी (R&D), डिजाइन और प्रतिभा के लिए उद्योग-आधारित पाइपलाइन
- घरेलू सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है
- आयात निर्भरता कम करता है

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का विस्तार

- बजटीय परिव्यय: ₹40,000 करोड़
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना

प्रभाव

- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स ईकोसिस्टम में मूल्यवर्धन को तेज करता है

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सुधार

- बॉन्डेड वेयरहाउस में घटकों के भंडारण हेतु गैर-निवासियों को सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) प्रदान करना, जिसमें लाभ मार्जिन चालान मूल्य के 2% तक सीमित होगा
- टोल विनिर्माताओं को पूंजीगत वस्तुएँ और टूलिंग की आपूर्ति करने वाले गैर-निवासियों को पाँच वर्ष की आयकर छूट

प्रभाव

- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को और गहरा करता है

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का निर्माण

राष्ट्रीय फाइबर योजना और टेक्स-इको पहल

- रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक रेशों और मानव निर्मित तथा नए जमाने के रेशों पर ध्यान
- एंड-टू-एंड घरेलू क्षमता का निर्माण करता है
- टेक्स-इको पहल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्रों के लिए

प्रभाव

- भारतीय वस्त्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है
- भारतीय वस्त्रों को वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करता है
- वस्त्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है

InvITs और REITs के माध्यम से रियल एस्टेट वैल्यू को अनलॉक करना

इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs)

इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी निधि

ऋणदाताओं को विवेकपूर्ण रूप से संतुलित आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है

प्रभाव

- **निर्माण के दौरान ऋणदाता का जोखिम कम करता है**
- निजी फंड को आकर्षित करता है
- इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की **समाप्ति तेज करता है**
- परियोजना की **व्यवहार्यता में सुधार** करता है

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों (सीपीएसई) की रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटीएस) के माध्यम से संपत्तियों के पुनर्चक्रण को तेज करना

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना का विकास

प्रभाव

- सीपीएसई की रियल एस्टेट संपत्तियों से धन अर्जित करता है
- परियोजनाओं के लिए पूंजी को मुक्त करता है
- संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन में सुधार करता है
- स्थिर लाभ (रिटर्न) उत्पन्न करता है

वैश्विक स्तर के फार्मा और बायोफार्मा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

बायोफार्मा-SHAKTI

अगले **5 वर्षों** के लिए **10,000 करोड़** रुपये का आवंटन

भारत को वैश्विक **बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तावित** करना

प्रभाव

- दवाओं की लागत को कम करता है
- **10 करोड़** से अधिक मधुमेह रोगियों को लाभ पहुंचाता है
- लगभग **14 लाख** कैंसर रोगियों को लाभ पहुंचाता है

समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञ

केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के पास समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञ होंगे

प्रभाव

- दवा अनुमोदन तेजी से होंगे
- **44%** खाली पदों वाले दवा निरीक्षक की रिक्तियों को संबोधित करता है

विकसित भारत के लिए हमारा दृष्टिकोण केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि कर्तव्य की यात्रा है

विमानन और रक्षा क्षेत्र में लागत कम करना और आत्मनिर्भरता का निर्माण

विमान निर्माण को बढ़ावा देना

विमान निर्माण के लिए आवश्यक घटकों पर मूल सीमा शुल्क से छूट

प्रभाव

- देशी विमान उत्पादन को बढ़ावा देता है
- विमानों के उत्पादन लागत को कम करता है

रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) को सुदृढ़ करना

आयात किए गए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट

घरेलू रक्षा MRO क्षमताओं को सुदृढ़ करता है

प्रभाव

- रक्षा विमानों के जीवनकाल रखरखाव लागत को कम करता है
- विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम करता है

निर्यात में बाधाओं को कम करना और व्यापार को तेज़ करना

समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

निर्दिष्ट समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इनपुट का शुल्क-मुक्त आयात

पिछले वर्ष के FOB निर्यात कारोबार के 1% से बढ़ाकर 3% किया गया

प्रभाव

- कार्यशील पूंजी के दबाव को कम करता है और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चमड़ा हब को बढ़ावा देता है

निर्यात समयसीमा का विस्तार

निर्यात समयसीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई

चमड़ा, वस्त्र और फुटवियर निर्यातकों का समर्थन करता है

प्रभाव

- निर्यातकों को मूल्य वर्धन और जटिल उत्पादन के लिए अधिक समय देता है
- अनुपालन के दबाव को कम करता है और लाभ मार्जिन सुधारने में मदद करता है

घरेलू टैरिफ क्षेत्र को SEZ बिक्री के लिए विशेष वन-टाइम उपाय

SEZ उत्पादन इकाइयाँ अब अपनी निर्यातित वस्तुओं का निर्धारित अनुपात घरेलू बाजार में रियायती शुल्क दर पर बेच सकती हैं

प्रभाव

- SEZ इकाइयों को राहत प्रदान करता है, क्षमता उपयोग को बढ़ाता है, और वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच संचालन का समर्थन करता है

अनुपालन को आसान बनाना और आईटी सेवाओं को बढ़ावा देना

एकल सेफ हार्बर श्रेणी

आई.टी सेवाओं को 15.5% के कॉमन सेफ़ हार्बर मार्जिन के साथ एक कैटेगरी में रखा जाएगा

प्रभाव

- वर्गीकरण विवादों को समाप्त करता है
- तेज़ कर निपटान सुनिश्चित करता है
- मध्यम और बड़ी आई.टी कंपनियों के लिए निश्चितता लाता है

उच्च पात्रता सीमा

आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ लेने की पात्रता सीमा को **₹ 300 करोड़** से बढ़ाकर ₹ 2,000 करोड़ किया जाए

प्रभाव

- लार्जर प्लेयर्स को लाभ का विस्तार करता है
- **मुकदमेबाजी/अनुपालन लागत को कम** करता है
- भारत में बड़ी **आईटी कंपनियों के निवेश को आकर्षित** करता है

तेज़ एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते

आईटी सेवाओं के लिए एकतरफा APA को तेज़ी से लागू करना

2 वर्षों के भीतर निष्कर्ष पर पहुँचने का लक्ष्य

अनुरोध पर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है

प्रभाव

- **लंबित ऑडिट को कम करता है**
- **ट्रांसफर प्राइसिंग में निश्चितता को तेज़ करता है**

स्वचालित नियम-आधारित सेफ हार्बर अनुमोदन

नियम-आधारित प्रक्रिया के **माध्यम से सेफ हार्बर** स्थिति को अनुमोदित करता है

कर अधिकारी द्वारा परीक्षा की आवश्यकता को हटाता है

कंपनी की इच्छा अनुसार **5 वर्षों** के लिए जारी रखा जा सकता है

प्रभाव

- अनुमोदन प्रक्रिया में होने वाली **देरी को समाप्त करता है**
- **अनुपालन** के बोझ को **आसान** और कम करता है

यह भारत का स्वर्णिम काल है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं

हरित ऊर्जा सुधार

कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस)

- उद्योगों को **कार्बन उत्सर्जन** को वातावरण में जाने से पहले पकड़ने में सक्षम बनाता है
- अगले **5 वर्षों** में **₹ 20,000** करोड़ का आवंटन
- सीमेंट, इस्पात और विद्युत जैसे कठिन-से-कम होने वाले क्षेत्रों के **डी-कार्बोनाइजेशन** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

प्रभाव

- इस्पात और सीमेंट जैसे उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों को अपना **कार्बन फुटप्रिंट** कम करने में मदद करता है
- सी.सी.यू.एस उपकरण निर्माण और सेवाओं के विशेषीकृत क्षेत्र में **नए रोजगार** के अवसर पैदा करता है

उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मूल्य को बाहर रखना

- बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर **कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं**
- बायोगैस के **संपूर्ण मूल्य** को **गणना से बाहर** रखा जाएगा

प्रभाव

- स्वच्छ परिवहन ईंधनों की **मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता** में सुधार करता है
- **सतत ऊर्जा** को अपनाने के लिए **प्रोत्साहित** करता है
- भारत के बायोगैस **पारिस्थितिकी तंत्र** के विकास का समर्थन करता है।

सौर इनपुट लागत को कम करना

- **सोडियम एंटिमोनेट** के आयात पर **मूल सीमा शुल्क से छूट**
- **सौर ग्लास** के निर्माण में उपयोग किया जाता है

प्रभाव

- सौर पैनलों की लागत को कम करता है
- पीएम सूर्य घर योजना के साथ नीतिगत समन्वय स्थापित करता है

लिथियम-आयन सेल्स पर मूल सीमा शुल्क से छूट

- "बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों **(BESS)** के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर छूट

प्रभाव

- **बैटरी भंडारण प्रणालियों** और **सौर ऊर्जा** के उत्पादन लागत को कम करता है
- **नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण** का प्रत्यक्ष समर्थन करता है

परमाणु ऊर्जा सुधार

- **2035 तक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं** के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क की छूट को सभी परमाणु संयंत्रों तक विस्तारित किया गया

प्रभाव

- **परमाणु ऊर्जा** परियोजनाओं के निर्माण की लागत को कम करता है
- भारत की ऊर्जा **सुरक्षा को सुदृढ़** करता है
- स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन को **सुविधाजनक** बनाता है
- **निजी भागीदारी** को बढ़ावा देता है

अब तक की यात्रा:
सुधार से राष्ट्र निर्माण की ओर

वैश्विक मंदी के बीच भारत एक 'उम्मीद की किरण'

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

GDP रैंकिंग

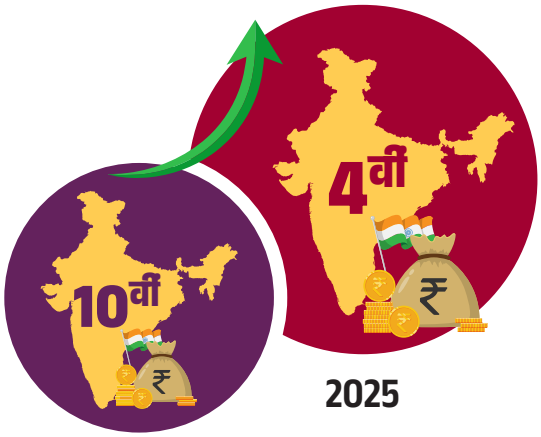

नॉमिनल GDP

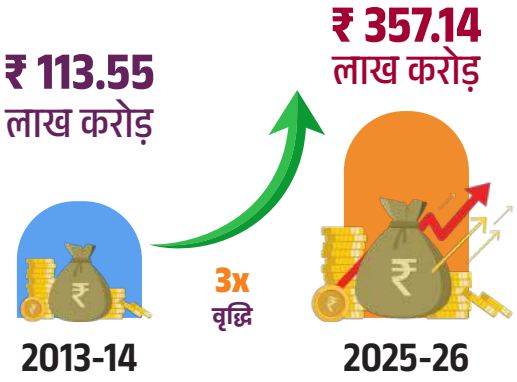

श्रम शक्ति भागीदारी दर

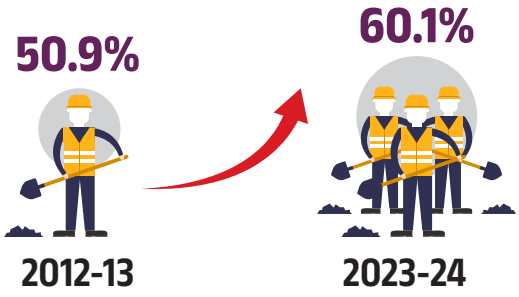

बेरोजगारी दर

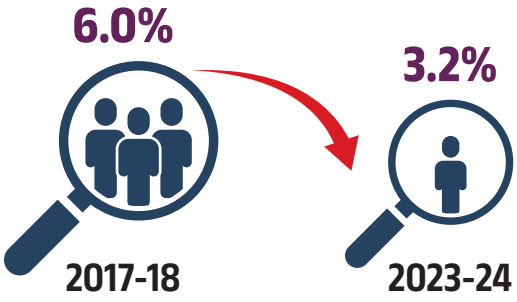

डिजिटल भुगतान लेनदेन

मात्रा

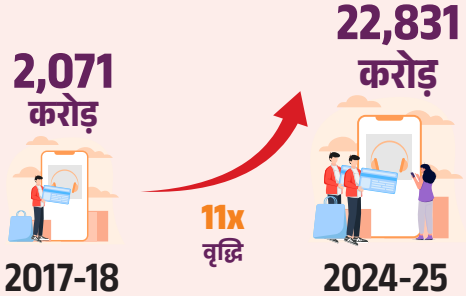

मूल्य

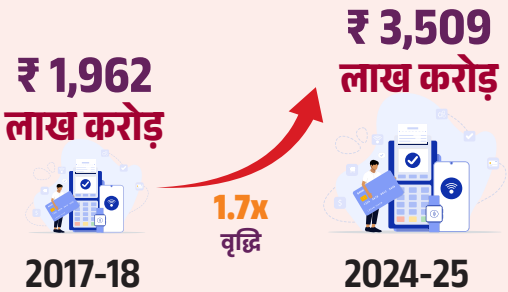

विदेशी मुद्रा भंडार

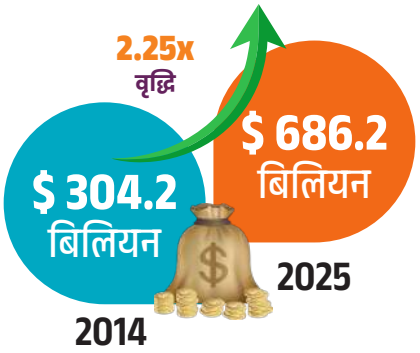

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

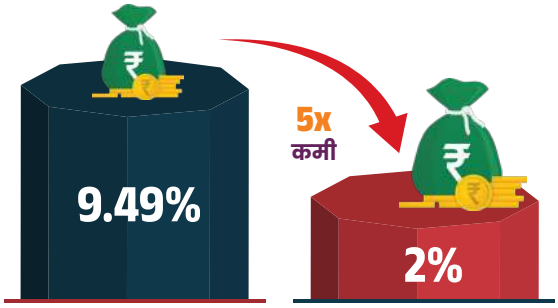

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

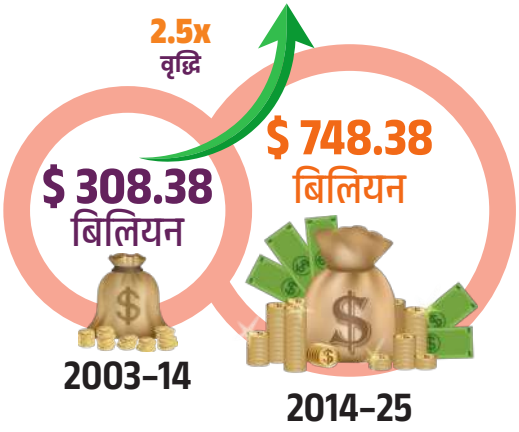

करंट अकाउंट डेफिसिट

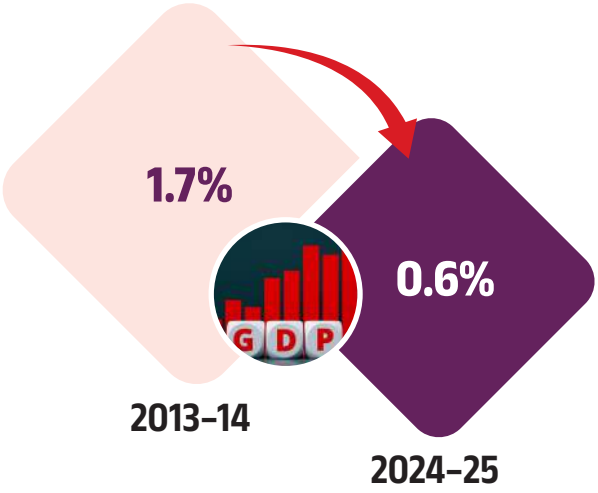

प्रति व्यक्ति आय

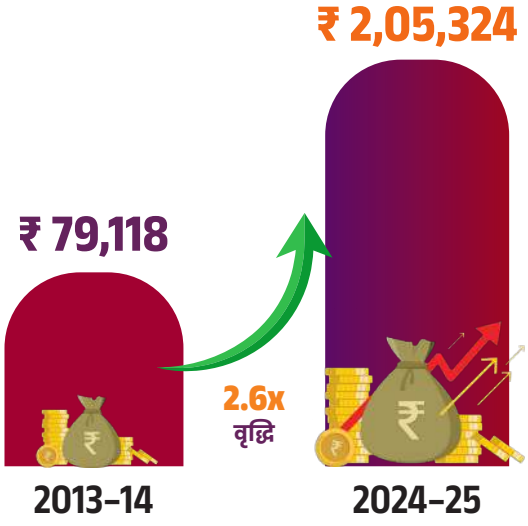

कुल सार्वजनिक ऋण के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण

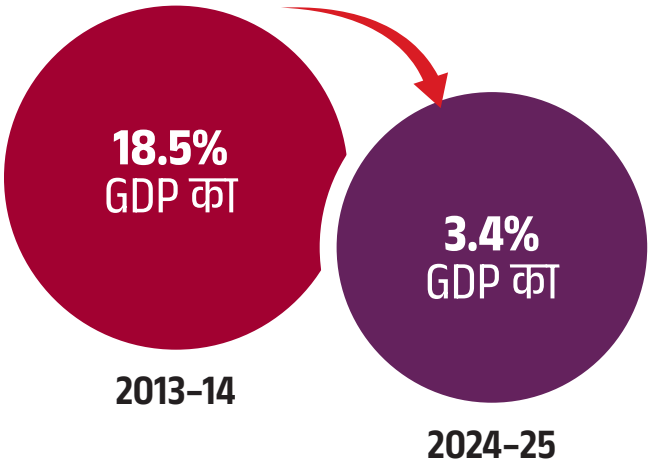

**सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास**

विकसित भारत का मार्ग

अगली पीढ़ी के जी.एस.टी सुधार

- दो-स्लैब स्तर **(5% और 18%)** में सरलीकृत
- आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाकर **5% या शून्य** किया गया
- नशीली और विलासिता की वस्तुओं पर **40% टैक्स**
- **एम.यू.वी कारों** के लिए जी.एस.टी में कमी और सेस को हटाया गया

प्रभाव

सरल टैक्स स्लैब और उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान देने से कर का बोझ कम हो

MSME की संशोधित परिभाषा

(टर्नओवर सीमा)	2020	2025
सूक्ष्म उद्यम	₹ 5 करोड़	₹ 10 करोड़
लघु उद्यम	₹ 50 करोड़	₹ 100 करोड़
मध्यम उद्यम	₹ 250 करोड़	₹ 500 करोड़

प्रभाव

इन संशोधनों से **एम.एस.एम.ई** को अपने कारोबार का विस्तार करने और **बेहतर संसाधनों** तक पहुँच बनाने में सहायता मिलेगी

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

5 कानूनों में 19 संशोधन; निवेशकों के हितों की रक्षा और लावारिस धन को निवेशक शिक्षा कोष में भेजना

प्रभाव

निवेशकों के दावा रहित राशि को **निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड** तक पहुंचाना

सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम, 2025

- बीमा कंपनियों में **100% FDI**
- लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी; **बीमा के प्रति जागरूकता** के लिए
- **पॉलिसीधारक शिक्षा** और **संरक्षण कोष** की स्थापना

प्रभाव

बीमा कवरेज का विस्तार करना और **पूंजी** एवं **तकनीकी उन्नयन** को सक्षम बनाना

नियामक सुधार

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

- **16 केंद्रीय अधिनियमों** (Acts) के अंतर्गत **288** दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है
- **'ईज ऑफ लिविंग'** (जीवन की सुगमता) के लिए **67** प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है
- पहली बार होने वाली छोटी गलतियों के लिए अब सजा के बजाय **चेतावनी** या **श्रेणीबद्ध नागरिक दंड (जुर्माना)** का प्रावधान किया गया है

प्रभाव

- यह सतत **आर्थिक विकास** का मार्ग प्रशस्त करता है
- व्यापार करने की **सुगमता को बढ़ाता है**

विनियमन और अनुपालन बोझ में कमी पर कार्यबल

केंद्र और राज्य के विभागों ने मिलकर **47,000 से अधिक अनुपालनों** को कम किया है

प्रभाव

अनुपालन लागत में कमी आने से व्यापारिक विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है

सिक्यौरिटीज़ मार्केट कोड, 2025

(वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया)

- यह **सिक्युरिटी बाजार** के **3 नियामक अधिनियमों** को समाप्त कर उनकी जगह लेगा
- **बाजार के दुरुपयोग** और गंभीर उल्लंघन को छोड़कर, अन्य विभिन्न प्रावधानों को **अपराध की श्रेणी से बाहर करता है**

प्रभाव

इससे **बाजार की कार्यक्षमता** और **नियमों के पालन में सुधार** होगा

> **पारदर्शिता ही सुशासन की कुंजी है**

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की समीक्षा

94% भारतीय मानकों को **'अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन'** और **'अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन'** के मानकों के अनुरूप बनाया गया है

अनुपालन को आसान बनाने के लिए **769 उत्पादों** को कवर करने वाले **187 गुणवत्ता** नियंत्रण आदेशों को बरकरार रखा गया है

नियमों को सरल करने के लिए प्रमुख सामग्रियों पर लागू **14 BIS गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों** को वापस लिया गया है

प्रभाव

MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए उत्पादन लागत में कमी आई है और घटिया गुणवत्ता वाले सामानों पर **सख्त निगरानी सुनिश्चित** हुई है

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (DPEPP) और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) सुधार

रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025: सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों के लिए लगभग **₹1 लाख करोड़** मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान करती है

- नवाचार और स्वदेशीकरण को विशेष प्रोत्साहन
- पुराने पड़ चुके **'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC)** की आवश्यकता को समाप्त किया गया

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में **₹1.54 लाख करोड़** का अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन दर्ज किया है

स्वदेशी रक्षा उत्पाद में प्रगति के आँकड़े (करोड़ ₹ में)

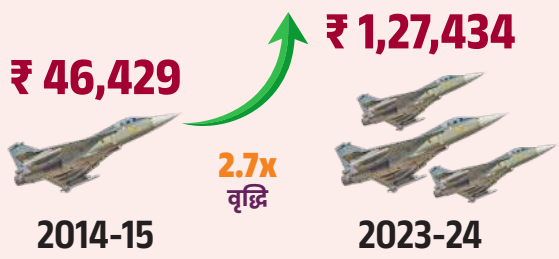

रक्षा निर्यात (करोड़ ₹ में)

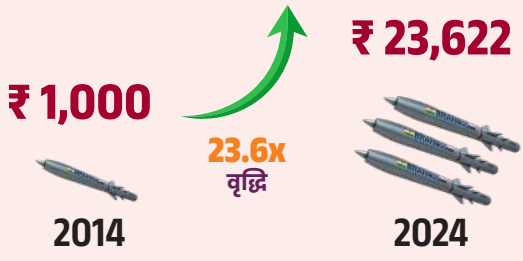

ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का मुख्य आधार स्वदेशी रक्षा तकनीक रही, जिसमें **'आकाश' हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली, लॉइटरिंग म्यूनिशन** (आत्मघाती ड्रोन) आदि जैसे आधुनिक हथियार शामिल रहे

श्रम शक्ति सुधार

ई.पी.एफ.ओ (EPFO) सुधार

कर्मचारी नामांकन योजना (EES)-2025: इसका उद्देश्य **भविष्य निधि** (EPF) के दायरे को बढ़ाना है ताकि अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके

पंजीकृत नियोक्ता अब **'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना'** का लाभ भी उठा सकते हैं

सुधारों में दावों का स्वत: निपटान और **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान** प्रणाली शामिल है

प्रभाव

अगले **2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार** पैदा करने के लिए **₹99,446 करोड़** का प्रोत्साहन (Incentive) पैकेज दिया गया है

श्रम संहिता, 2025 का कार्यान्वयन

29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर **4 सरल श्रम संहिताओं** में बदल दिया गया है

'गिग' और **प्लेटफॉर्म श्रमिकों** (जैसे डिलीवरी पार्टनर) को भी अब सामाजिक सुरक्षा

महिलाओं को उनकी सहमति और **सुरक्षा सुनिश्चित** होने पर सभी क्षेत्रों में **नाइट शिफ्ट** में काम करने की अनुमति दी गई है

काम के घंटे प्रतिदिन **8-12 घंटे** और प्रति सप्ताह अधिकतम **48 घंटे** निर्धारित किए गए हैं

प्रभाव

यह भारत के कार्यबल के लिए बेहतर **वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा** और **कल्याण** सुनिश्चित करता है

यह सुधार श्रमिकों के हितों और **उद्योगों की जरूरतों** के बीच एक सही संतुलन बनाता है

सुरक्षा भी, सरलता भी

भारत के निर्यात का विविधीकरण

व्यापार समझौते

भारत - न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट: 100% भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी, 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर का निवेश

भारत - यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता : 99% भारतीय निर्यात पर से टैरिफ हटाया गया, व्यापार का मूल्य 56 बिलियन डॉलर आँका गया है

भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट: 96.6% वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त किए जाएंगे, जिससे भारत को 27 यूरोपीय संघ देशों में 97% टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी

प्रभाव

भारतीय वस्तुओं को **व्यापक वैश्विक बाजार** प्रदान करके निर्यात के **विविधीकरण** और **दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा** को बढ़ावा देना

व्यापार संबंधी सुधार

निर्यात संवर्धन मिशन

निर्यात प्रोत्साहन

एम.एस.एम.ई. के लिए सस्ती दरों पर व्यापार वित्त उपलब्ध कराना

निर्यात दिशा

ऐसे गैर-वित्तीय कारक जो बाजार की तैयारी और क्षमता को बढ़ाते हैं

कुल परिव्यय:

₹25,060 करोड़

(वित्त वर्ष 2025-31)

प्रभाव

बेहतर वित्तीय पहुँच के माध्यम से **एम.एस.एम.ई** और **नए निर्यातकों** के लिए निर्यात वृद्धि को गति देना

सुधार उन्मुख नीतिगत निर्णय

लचीले कोयला लिंकेज के लिए 'कोलसेतु' नीति

गैर-रेलवे साइडिंग लिंकेज नीति के अंतर्गत नीलामी आधारित **विंडो** शुरू की गई

प्रभाव

'कोलसेतु' निलामी आधारित विंडो ने कोयला लिंकेज में **पारदर्शिता** और **लचीलेपन** में सुधार किया है

ई-निलामी बुकिंग में वृद्धि (मिलियन टन)

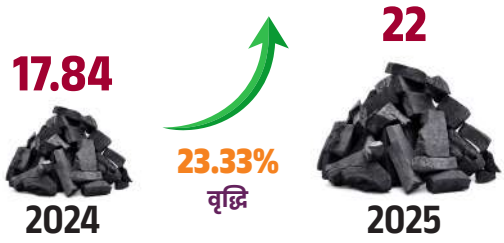

मैन-मेड फाइबर और तकनीकी वस्त्रों के लिए संशोधित PLI योजना

न्यूनतम वृद्धिशील टर्नओवर मानदंड

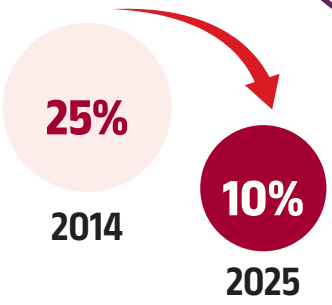

प्रभाव

मैन-मेड फाइबर (MMF) और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, **विनिर्माण का विस्तार** करना और आयात पर निर्भरता कम करना

सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) अधिनियम, 2025 और परमाणु ऊर्जा मिशन

परमाणु क्षमता में वृद्धि (गीगावाट)

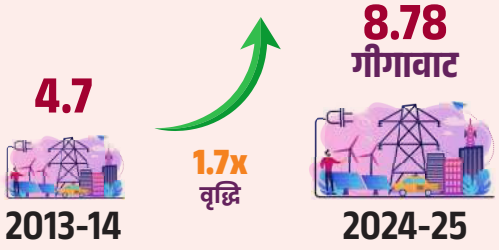

बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट)

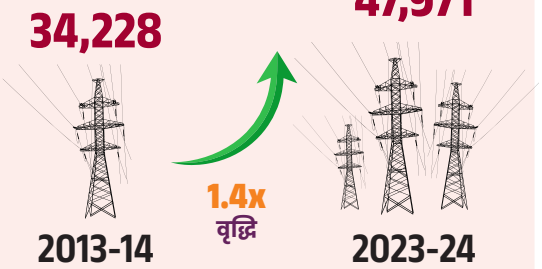

प्रभाव

2031-32 तक **22.38 गीगावाट** और 2047 तक **100 गीगावाट** परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य

नीति में सुधार, प्रगति का रूपांतरण

CAR-1

आधारभूत संरचना

पिछले एक दशक में आधारभूत संरचना का विकास सरकार की विकास रणनीति का प्रमुख आधार रहा है। **भारतमाला परियोजना, पीएम गतिशक्ति** और क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) जैसी पहलों के माध्यम से **सड़कों, रेल, बंदरगाहों और विमानन क्षेत्र में व्यापक निवेश किया गया है**, जिससे लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में तेजी आई है।

इस केंद्रित प्रयास से शहरी परिवहन और यातायात सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, **कवच रेल सुरक्षा प्रणाली**, **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** के अंतर्गत मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तथा **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम** विकसित भारत के लिए आधुनिक, दक्ष और भविष्य-उन्मुख आधारभूत संरचना के निर्माण की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

- स्वदेश दर्शन योजना
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
- अंतर्देशीय जल कार्गो

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

प्रमुख मंत्रालयों के लिए बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय

के लिए बजटीय आवंटन

₹ 2,57,641 करोड़

2013-14

4.75x वृद्धि

₹ 12,21,821.3 करोड़

2026-27

सड़क परिवहन और राजमार्ग

10x वृद्धि

₹ 31,302.14
वर्ष 2013-14

₹ 3,09,875
वर्ष 2026-27

आवास और शहरी मामले

57.6x वृद्धि

₹ 1,486.02
वर्ष 2013-14

₹ 85,522
वर्ष 2026-27

रेलवे

10.8x वृद्धि

₹ 26,000
वर्ष 2013-14

₹ 2,81,377
वर्ष 2026-27

इस्पात

4x वृद्धि

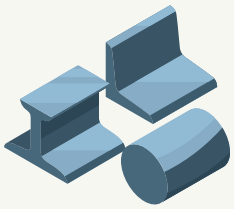

₹ 112.87
वर्ष 2013-14

₹ 443
वर्ष 2026-27

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग

3x वृद्धि

₹ 1,712.67
वर्ष 2013-14

₹ 5,164
वर्ष 2026-27

ऊर्जा

3x वृद्धि

₹ 10,073.07
वर्ष 2013-14

₹ 29,997
वर्ष 2026-27

> आज बुनियादी ढांचे में निवेश आने वाले दशकों के लिए भारत की वृद्धि का निर्धारण करेगा

स्केलेबल औद्योगिक विकास

के लिए प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पार्क

चुनौती मोड में **मेगा टेक्सटाइल पार्कों** का विकास

चुनौती मार्ग के माध्यम से समर्पित रासायनिक पार्कों का विकास

बजटीय आवंटन

₹ 600 करोड़

प्रभाव:

MSME एकीकरण और बड़े पैमाने पर औद्योगिक रोजगार को मजबूत करना

बायो फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना

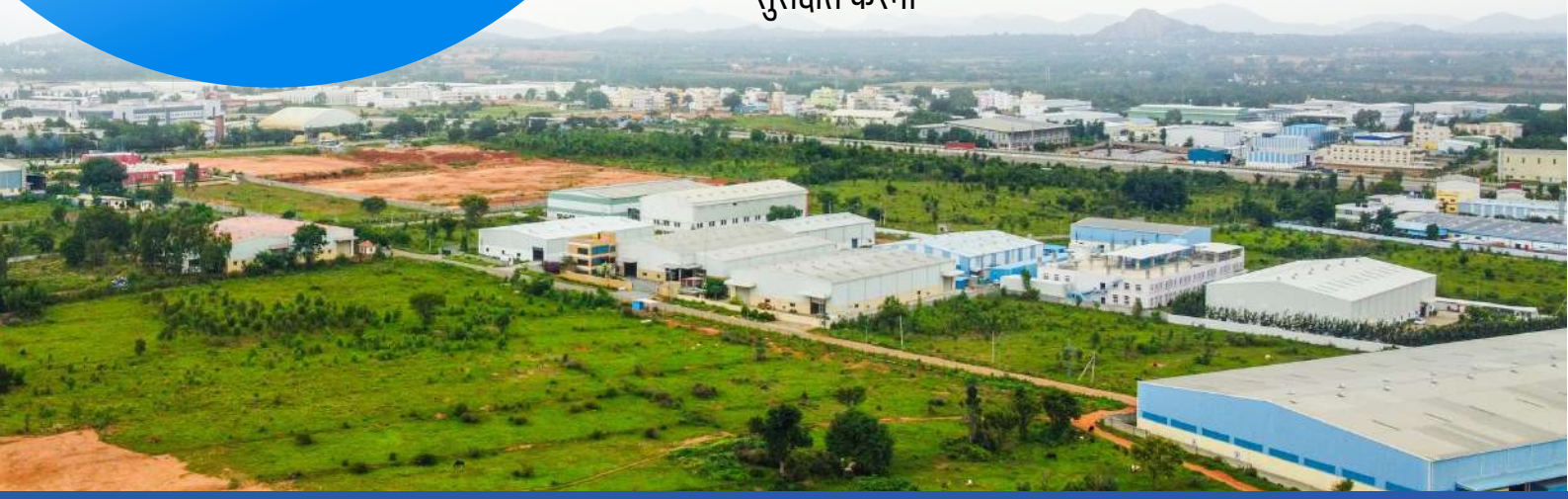

शहरी आर्थिक क्षेत्र

बजटीय आवंटन

₹ 5,000 करोड़

प्रति क्षेत्र 5 वर्षों में

शहरों की क्षमता को बढ़ाना

विशिष्ट विकास चालकों के आधार पर शहरी के आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करना

प्रभाव:

मेट्रो शहरों से परे नए शहरी विकास इंजन

संतुलित क्षेत्रीय विकास

भारत की विकास गति को सुदृढ़ करने वाली उत्कृष्ट अवसंरचना

इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर

गतिशीलता के इंजन और क्षेत्रीय आर्थिक क्लस्टरिंग के रूप में

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
पूर्व में दनकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ना

खनिज समृद्ध क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले नए 20 जलमार्गों का संचालन

प्रभाव
जलमार्ग आधारित कार्गो आवाजाही के माध्यम से रसद लागत में 40-50% की कमी

विकास संपर्कों के रूप में **7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का** विकास

- मुंबई-पुणे
- पुणे-हैदराबाद
- हैदराबाद-चेन्नई
- चेन्नई-बेंगलुरु
- दिल्ली-वाराणसी
- वाराणसी-सिलीगुड़ी
- हैदराबाद-बेंगलुरु

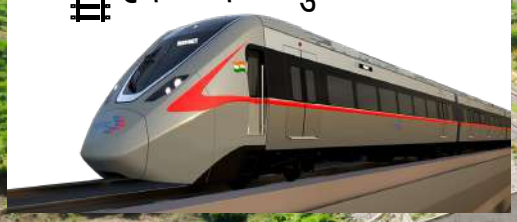

दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) कॉरिडोर
ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकास

पर्यटन बुनियादी ढांचा

मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए हब

आयुष केंद्र, नैदानिक बुनियादी ढांचा और सुविधा केंद्र

प्रभाव:

- एकीकृत स्वास्थ्य पर्यटन अवसंरचना का निर्माण
- भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनाएगा

विरासत और संस्कृति पर्यटन का बढ़ावा

क्यूरेटेड वॉकवे के लिए 15 पुरातात्विक स्थलों को खोला जाना

प्रभाव:

- विरासत स्थलों को सांस्कृतिक आर्थिक संपत्तियों में परिवर्तन

सी-प्लेन व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना

स्वदेशी सी-प्लेन निर्माण का समर्थन

प्रभाव:

- उच्च परिचालन ओवरहेड्स को कम करना
- नीली अर्थव्यवस्था पर्यटन का समर्थन

SASCI योजना राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता

बजटीय आवंटन:
₹ 2 लाख करोड़

प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को वैश्विक स्तर पर विकसित करना

स्थानीय विरासत को वैश्विक गंतव्यों में बदलना

प्रभाव:

क्षेत्रीय रोजगार और विदेशी मुद्रा आय पर गुणक प्रभाव

स्थानीय शोधकर्ताओं और सामग्री रचनाकारों के लिए नौकरियां

तटीय कार्गो और उत्तर-पूर्व का विकास

तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना: तटीय क्षेत्रों में रेल और सड़क से कार्गो की आवाजाही को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन

जहाज मरम्मत इको-सिस्टम: वाराणसी और पटना में परिचालन दक्षता और जहाजों की लंबी उम्र के लिए समर्थन

प्रभाव

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है
- जहाजों के डाउनटाइम और रखरखाव लागत को घटाता है

उत्तर-पूर्व भारत के विकास के लिए बुनियादी ढांचा

- **5 पूर्वोदय राज्यों** में **5 पर्यटन स्थलों** का निर्माण
- **अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा** में **बौद्ध सर्किट** का विकास
- बढ़ी हुई गतिशीलता के लिए **4,000 ई-बसों का प्रावधान**

पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव

प्रभाव:

- भारत-आसियान व्यापार संपर्क को मजबूत करना
- पूर्वोत्तर की बौद्ध मंदिरों, मठों एवं जीवंत संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देता है
- क्षेत्रीय रोजगार पैदा करके युवाओं का पलायन रोकना

एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर एवं शहरी विकास अवसंरचना

200 पुराने औद्योगिक समूहों का कायाकल्प

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (INVITS), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITS) तथा NIIF और NABFID जैसी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करता है

प्रभाव

MSMES को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना

टियर-2 और टियर-3 शहरों को नए विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना

आत्मनिर्भर विनिर्माण और कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए योजनाएँ

उच्च मूल्य एवं तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरण के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु योजना **(बजटीय आवंटन: ₹ 200 करोड़)**

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु कंटेनर विनिर्माण योजना **(बजटीय आवंटन: 5 वर्षों में ₹ 10,000 करोड़)**

उच्च-परिशुद्धता घटकों के स्थानीय डिज़ाइन, परीक्षण एवं निर्माण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा हाई-टेक टूल रूम की स्थापना

प्रभाव

सहायक उद्योगों को सुदृढ़ करते हुए महत्वपूर्ण रोजगार गुणक का सृजन करता है

"री-पोज़िशनिंग" लागत को समाप्त कर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है

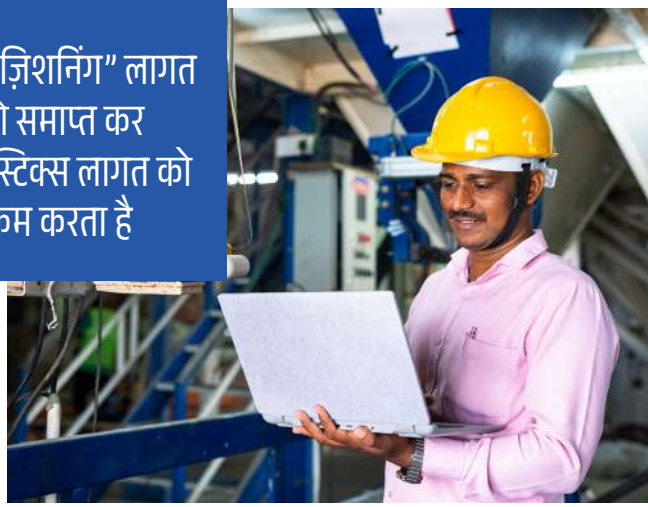

शहरों को आर्थिक गतिविधियों के गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और नगर निकायों को उनके रूपांतरण की सक्रिय योजना बनानी चाहिए

अब तक की यात्रा:
इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की बुनियाद

परिवर्तनकारी अवसंरचना का पिछले एक दशक में विकास

विश्व-स्तरीय यातायात बुनियादी ढांचे का सृजन

बेमिसाल गति से हवाई अड्डों का निर्माण

2014 से **13 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों** का निर्माण/संचालन किया गया है

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना -उड़ान के अंतर्गत **649 मार्ग** संचालित किए गए और **93 हवाई अड्डों** को जोड़ा गया

हवाई अड्डे

74 (2014) → 2.2x वृद्धि → 163 (2025)

एयरलाइन रूट

209 (2014) → 2.9x वृद्धि → 615 (2024)

प्रति वर्ष कुल हवाई अड्डा यात्री क्षमता

20 करोड़ (2014) → 2.5x वृद्धि → >50 करोड़ (2024)

घरेलू एयरलाइन क्षमता

79 लाख (2014) → 2x वृद्धि → 1.55 करोड़ (2024)

घरेलू हवाई यात्री यातायात

10.38 करोड़ (2014) → 2.2X वृद्धि → 22.81 करोड़ (2024)

डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय रूट

25 करोड़ (2014) → 1.4x वृद्धि → 35 करोड़ (2024)

रेलवे कनेक्टिविटी

बढ़ाना और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना

लिंक हॉफमैन बुश (LHB) कोच उत्पादन

2004-14
2,300

2014-25
>42,600

18.5x वृद्धि

ब्रॉड गेज विद्युतीकरण

2004-14
1.42

10.5x वृद्धि (किमी/दिन)

2014-25
15

25 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 100% विद्युतीकृत हैं, कोई भी ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर (RKMS) विद्युतीकरण के लिए शेष नहीं है

ब्रॉड गेज लाइनों के 99.2% RKMS का विद्युतीकरण हो चुका है

गति शक्ति कार्गो से राजस्व

2024-25
₹ 12,608.05

4.3x वृद्धि (₹ करोड़ में)

2022-23
₹ 2,901.9

2019-2024: 695.2 मिलियन टन माल ढुलाई से **₹7,02,372.3 करोड़** का राजस्व प्राप्त हुआ

PM GatiShakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों ने रेल द्वारा अतिरिक्त **267.2 करोड़ टन** माल ढुलाई की, जिससे **14.3 करोड़ टन CO_2 उत्सर्जन की बचत हुई।**

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यातायात

2023-24
247

+42% वृद्धि (ट्रेनें/प्रतिदिन औसत)

2024-25
352

वित्त वर्ष 2025-26 में **164 वंदे भारत** ट्रेन रूट संचालित किए

स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच)

ट्रैकसाइड कवच का कार्यान्वयन **15,512 किमी रेलवे मार्ग** पर किया गया

2,000 किमी से अधिक रेलवे रूट पर **'कवच'** चालू किया गया

4,154 इंजनों (लोकोमोटिव) पर सफलतापूर्वक स्थापित किया

निर्बाध गतिशीलता के लिए **शहरी पारगमन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा** देना

नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) -
180 किमी
प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई-स्पीड क्षेत्रीय ट्रांजिट प्रणाली

आर.आर.टी.एस **(RRTS)** शहरी गतिशीलता, रियल एस्टेट विकास और बढ़ते निवेशक विश्वास के चालक के रूप में उभर रहा है

8 आर.आर.टी.एस कॉरिडोर

3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर

एन.सी.आर-2032 परिवहन योजना

दिल्ली
- गाजियाबाद – मेरठ
- गुरुग्राम – शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़
- पानीपत

अनुमानित कुल लागत **₹ 65,000 करोड़**

मेट्रो नेटवर्क में वृद्धि

5 शहरों में **248 किमी** (2014) → 4x वृद्धि → 23 शहरों में **1,013 किमी** (2025)

दैनिक यात्री संख्या

28 लाख (2013-14) → 4x वृद्धि → **1.1 करोड़** (2025)

नई मेट्रो लाइनों का निर्माण

0.7 किमी/माह (2014) → 8.8x वृद्धि → **6** किमी/माह (2025)

एकीकृत औद्योगिक एवं शहरी बुनियादी ढांचा विकास

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम इसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को **'स्मार्ट सिटी'** के रूप में विकसित करना है

12 नए प्रोजेक्ट प्रस्तावों के अंतर्गत स्वीकृति दी गई, जिसमें **₹ 28,602 करोड़** का निवेश किया जाएगा

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल **8,067** परियोजनाओं में से **94% परियोजनाएं** पूरी हो चुकी हैं।इसमें अब तक **₹ 1.6 लाख करोड़** का निवेश किया जा चुका है।

रिकॉर्ड तोड़ गति से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई

1.6x वृद्धि

91,287 किमी
2013-14

1,46,560 किमी
2024-25

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति

3x वृद्धि

11.6 किमी/प्रतिदिन
2013-14

34 किमी/प्रतिदिन
2025

हाई-स्पीड कॉरिडोर/एक्सप्रेसवे

32.8x वृद्धि

93 किमी
2013-14

3,052 किमी
2025

भारतमाला परियोजना

निवेश
₹ 46,000 करोड़

35
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नियोजित हैं

2024-25 तक
20,378 किमी
लंबे राजमार्ग का निर्माण पूरा किया गया

शिपिंग और समुद्री क्षेत्र का विकास

राष्ट्रीय जलमार्गों में निवेश
वृद्धि 9.3x
2014: ₹ 183 करोड़
2025: ₹ 1,700 करोड़

क्रूज यात्रियों की संख्या
वृद्धि 5.8x
2014: 84,000
2025: 5 लाख

संचालित जलमार्ग
वृद्धि 9.7x
2014: 3
2025: 29

अंतर्देशीय जल कार्गो
वृद्धि 8x
2014: 18 MMT
2025: 146 MMT

भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे का कायाकल्प

यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक

54th 2021

39th 2024

विदेशी मुद्रा आय

₹ 2,93,033 करोड़
2025

2.7x वृद्धि

₹ 1,07,563 करोड़
2014

स्वदेश दर्शन योजना

बजटीय आवंटन
स्वीकृत राशि
₹ 5,290.3 करोड़
(2025 तक)

76 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं

75 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं

स्वदेश दर्शन 2.0

बजटीय आवंटन
स्वीकृत राशि
₹ 2,208.3 करोड़
(2025 तक)

53 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं

प्रसाद योजना

बजटीय आवंटन:
₹ 245 करोड़
स्वीकृत राशि

₹ 1,726.7 करोड़
वित्त वर्ष 2026 तक

54 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं

32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

प्रयासों के सुखद परिणाम

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से अब तक मंत्रियों और मशहूर हस्तियों सहित **5.5 करोड़** से **अधिक श्रद्धालु** दर्शन कर चुके हैं

महाकुंभ के माध्यम से ₹ 3 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है

एक सतत भविष्य में निवेश

स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता

2014: 3 GW
2025: 129 GW

वृद्धि **43x**

भारत में एथेनॉल मिश्रण

2014: 1.5%
2025: 20%

वृद्धि **13x**

गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता

2014: 76.38 GW
2025: 266.78 GW

वृद्धि **3.5x**

बिजली की कमी

2014: 4.2%
2025: 0.1%

97.6% तक कमी कम हुई है

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसका लक्ष्य **2030** तक **6 लाख** रोजगार पैदा करना और सालाना **50 MMT** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ने **₹ 1,55,000 करोड़** की विदेशी मुद्रा बचाई है और शुद्ध CO_2 उत्सर्जन में 790 लाख मीट्रिक टन की कमी की है

PLI योजना उच्च दक्षता वाले **सौर पीवी मॉड्यूल** के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **₹ 24,000 करोड़** की योजना

सोलर पार्क में वृद्धि

34
2014

55
2025

वृद्धि **1.7x**

स्वीकृत क्षमता 20 GW से बढ़कर **40 GW** हो गई है

PROJECT HEAD
DIRECTOR PROJECT
WATCH YOUR STEP

वंचित वर्ग

लंबे समय तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित वर्ग विकास की मुख्यधारा से दूर रहे। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में कमी तथा **सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुँच** के कारण अनेक समुदाय राष्ट्रीय प्रगति में पूर्ण भागीदारी नहीं कर सके, जबकि उनका **सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है**।

पिछले एक दशक में सरकार ने वंचित वर्गों के लक्षित सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। **पीएम जनमन (विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए)**, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति बहुल गांवों हेतु पीएम-अजय, तथा **पीएम श्रेयस और पीएम यशस्वी जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं** के माध्यम से समावेशी विकास को गति मिली है। आवास, बुनियादी ढाँचा, आजीविका और **अधिकारों की मान्यता** से जुड़े प्रयासों के साथ ये पहल इस स्पष्ट सोच को दर्शाती हैं कि भारत का परिवर्तन तभी सार्थक है जब सबसे **वंचित वर्गों को विकास की अग्रिम पंक्ति में लाया जाए**।

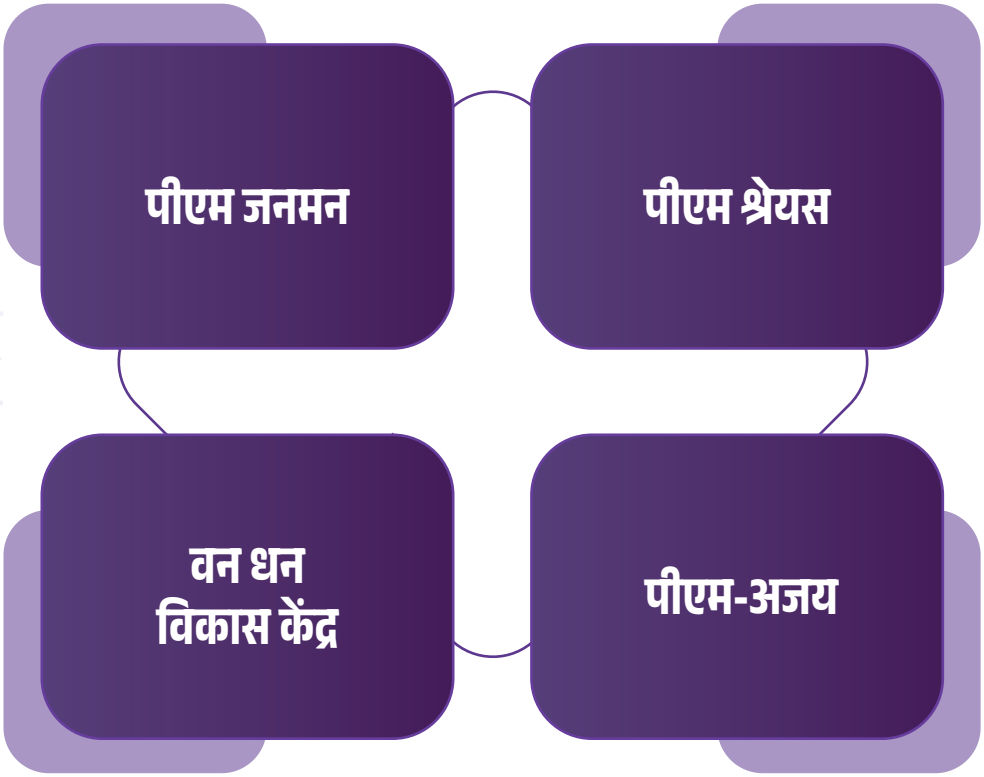

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन

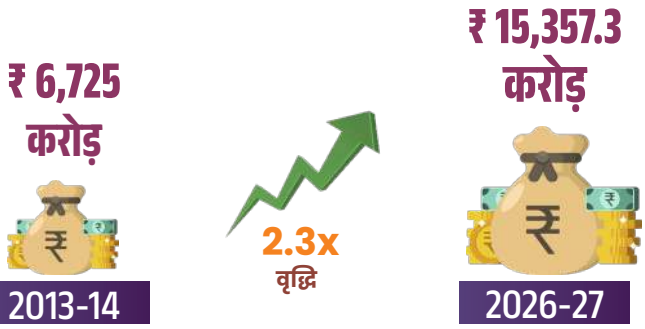

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए **बजटीय आवंटन**

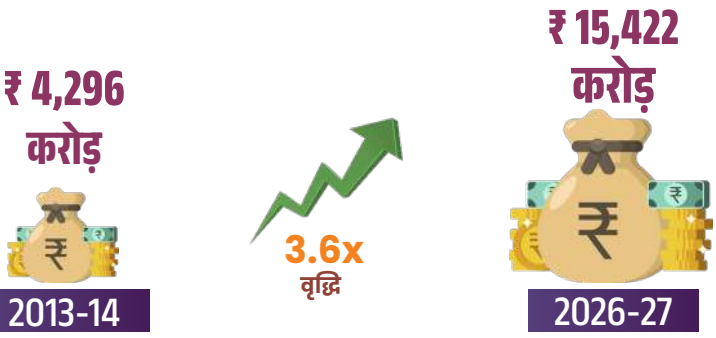

"वंचितों" के लिए प्रमुख प्रावधान

दिव्यांगजन कौशल योजना (बजटीय आवंटन: ₹200 करोड़)
IT, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC), आतिथ्य (Hospitality) और खाद्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण

प्रभाव निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

दिव्यांग सहारा योजना (बजटीय आवंटन: ₹ 100 करोड़)
कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के माध्यम से सहायक उपकरणों के लिए सहायता। इसमें R&D, AI एकीकरण और प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का सुदृढ़ीकरण शामिल है

प्रभाव दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपकरणों की लागत कम होगी

तेंदू पत्तों पर TCS में कमी
तेंदू पत्तों पर 'स्रोत पर कर संग्रह' (TCS) को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है

प्रभाव आदिवासी संग्रहकर्ताओं और व्यापारियों पर बोझ कम होगा

> **वंचितों का सशक्तिकरण**

अब तक की यात्रा:
वंचितों को प्राथमिकता

व्यापक ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN)

बजटीय आवंटन:
₹ 100 करोड़

75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का **सामाजिक-आर्थिक** विकास।

योजना के तहत हुई प्रगति

- **2.38 लाख** पक्के मकान बनकर तैयार
- **825 किमी** सड़क निर्माण पूर्ण
- **694** मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित
- **7712 गाँवों** में जल आपूर्ति
- **2084 आंगनवाड़ी केंद्र** संचालित
- **111 छात्रावासों** का निर्माण और संचालन
- **1.34 लाख** घरों का विद्युतीकरण
- **2944 मोबाइल टावरों** की स्थापना

पिछड़ों का उत्थान, राष्ट्र का कल्याण

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY)

बजटीय आवंटन:
₹ 2,140 करोड़
लाभार्थी: **2,48,570**

अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति (SC) समुदायों में गरीबी कम करना

योजना के अंतर्गत घटक:

12,964 अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों को 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकास

1461.13 करोड़ का सहायता अनुदान जारी (2.48 लाख लाभार्थियों के लिए)

90 नए छात्रावास स्वीकृत (10,649 लाभार्थियों के लिए)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
बजटीय आवंटन: **₹ 7,150 करोड़**
लाभार्थी: **1.38 लाख**

- दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

स्वीकृत स्कूल

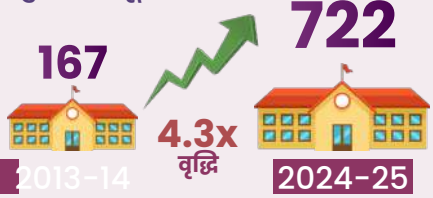

प्रभाव

1.38 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति - एस.सी (PM SHREYAS-SC)

बजटीय आवंटन:
₹ 495 करोड़

वर्ष 2024-25 में, **9,371 एस.सी** और ओ.बी.सी छात्र लाभार्थियों को **₹ 390.49 करोड़** की छात्रवृत्ति जारी की गई

इस योजना में 4 उप-योजनाएँ शामिल है:

एस.सी. के लिए **टॉप क्लास स्कॉलरशिप**

नि:शुल्क कोचिंग योजना एस.सी. और ओबीसी छात्रों के लिए

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना एस.सी. के लिए

राष्ट्रीय फेलोशिप एस.सी. छात्रों के लिए

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक ट्राइबल स्कॉलरशिप

9.08 लाख
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

18.16 लाख
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

पीएम यशस्वी योजना (PM YASASVI)

बजटीय आवंटन: **₹ 2,320 करोड़**

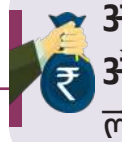

ओ.बी.सी, ई.बी.सी, डी.एन.टी के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: 45.14 लाख लाभार्थी; **₹ 894.86 करोड़** वितरित

ओ.बी.सी छात्रावास: 1,700 लाभार्थी; **₹ 37.05 करोड़** वितरित

टॉप-क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप (ओ.बी.सी, ई.बी.सी, डी.एन.टी):
22,389 लाभार्थी; **₹ 275.71 करोड़** वितरित

जब वंचित जुड़ता है, तब विकास पूरा होता हैं

अधिवास विकास
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

बजटीय आवंटन:
₹ 830 करोड़

लाभार्थी:
12 लाख

वन धन विकास केंद्र (VDVK)
स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराना

प्रभाव

लघु वनोपज की खरीद के लिए
4,030 VDVK केंद्र स्वीकृत

₹ 89.14 करोड़ इनके लिए स्वीकृत:

1,316 हाट बाज़ार

603 स्टोरेज यूनिट्स

22 प्रोसेसिंग यूनिट्स

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)

10 राज्यों ने आधिकारिक तौर पर **पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों** को अधिसूचित **किया**

प्रभाव

77,564 गाँव, 22,040 पंचायतें, 664 ब्लॉक और **45 जिले** पूरी तरह से कवर **63 आंशिक रूप से कवर किए गए जिलों** के साथ

वनाधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन पिछले 11 वर्षों में

व्यक्तिगत पट्टे का वितरण

2014	वृद्धि	2025
14.36 लाख	1.7x	24 lakh

सामुदायिक पट्टे का वितरण

2014	वृद्धि	2025
23,000	1.7x	1.21 लाख

क्लेम का निपटारा

2014	वृद्धि	2025
25 लाख	1.7x	43.72 लाख

निहित भूमि क्षेत्र (एकड़)

2014	वृद्धि	2025
55 लाख एकड़	1.7x	232.66 लाख एकड़

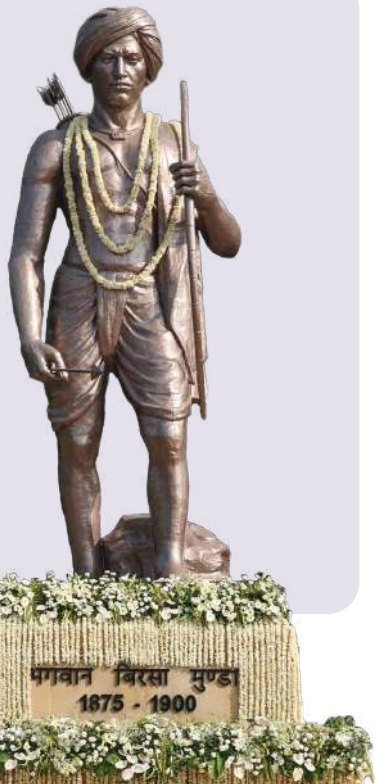

आजीविका और सामाजिक उत्थान

पीएम विश्वकर्मा योजना

बजटीय आवंटन: ₹ 3860.9 करोड़

लाभार्थी: 30 लाख कारीगर नामांकित

- **25 पारंपरिक व्यवसायों** से जुड़े कारीगरों का उत्थान
- **कम ब्याज दर** पर **₹ 2 लाख** तक का ऋण
- **₹ 1 लाख** तक का बिना गारंटी ऋण
- कुल **₹ 41,188 करोड़** के **4.7 लाख** से ज़्यादा लोन स्वीकृत

प्रभाव

- कई हस्तशिल्प उद्योगों में पारंपरिक शिल्प कौशल को संरक्षित किया
- मार्केटिंग के अवसर और बिना गारंटी वाले क्रेडिट तक आसान पहुंच

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

ऋण वितरित: **₹ 188.2 करोड़**

लाभार्थी: **25,927**

वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS)
बजटीय आवंटन: ₹ 50.3 करोड़

आजीविका ऋण पर **5% ब्याज सब्सिडी**

एस.सी के लिए वितरित राशि: **₹ 24.72 करोड़**

लाभार्थी: **1.96 लाख**

ओ.बी.सी के लिए वितरित राशि: **₹ 19.97 करोड़**

लाभार्थी: **1.93 लाख**

वेंचर कैपिटल फंड

एस.सी उद्यमियों के लिए

स्वीकृत:	140 कंपनियों को ₹ 587.66 करोड़ स्वीकृत
वितरण:	119 कंपनियों को ₹ 419.85 करोड़

अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन (एस.सी छात्रों के लिए)

स्वीकृत:	104 कंपनियों को ₹ 26.11 करोड़ स्वीकृत
वितरण:	86 कंपनियों को ₹ 12.72 करोड़

वेंचर कैपिटल फण्ड फॉर प्रमोटिंग बिज़नेस अमंग बैकवर्ड क्लासेज़

स्वीकृत:	28 कंपनियों को ₹ 122.88 करोड़ स्वीकृत
वितरण:	16 कंपनियों को ₹ 61.50 करोड़

देश के वंचितों का उत्थान, विकसित भारत का आधार।

भगवान बिरसा मुण्डा
1875 - 1900

मध्यम वर्ग

पिछले एक दशक में भारत के मध्यम वर्ग के विस्तार के साथ उसकी आकांक्षाएँ भी बढ़ी हैं, और सरकार ने लगातार उनके **वित्तीय एवं सामाजिक बोझ को कम करने का प्रयास** किया है। **कर स्लैब के युक्तिकरण**, बढ़ी हुई कर छूट सीमा तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं, **स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में जी.एस.टी** सुधारों के माध्यम से परिवारों की आय में वृद्धि हुई है और भविष्य की योजना बनाने में उनका विश्वास अधिक मजबूत हुआ है।

वित्तीय राहत से आगे बढ़ते हुए आयुष्मान भारत, **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के अंतर्गत किफायती आवास, एन.पी.एस और यू.पी.एस के माध्यम से पेंशन सुरक्षा तथा **पीएम सूर्य घर** जैसी योजनाओं ने **मध्यम आय वर्ग की दीर्घकालिक सुरक्षा** को सुदृढ़ किया है। ये सभी उपाय भारत की विकास यात्रा में **मध्यम वर्ग को एक मजबूत स्तंभ** के रूप में सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

- पीएम सूर्य घर योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- उड़ान
- सुकन्या समृद्धि योजना

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

मध्यम वर्ग के लिए क्या सस्ता हुआ है?

क्या सस्ता हुआ	कैसे	इसका क्या अर्थ है
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ब्याज भुगतान	शून्य आयकर, शून्य टी.डी.एस (TDS)	पीड़ितों को बिना किसी देरी के पूरी क्षतिपूर्ति राशि + ब्याज प्राप्त होगा
विदेशी यात्रा टूर पैकेज	टी.सी.एस (TCS) दर घटाकर फ्लैट 2% की गई पिछले 5% या 20% से	बुकिंग के समय कम पैसा फंसेगा, जिससे विदेश यात्रा अधिक सस्ती हो जाएगी
विदेशी शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण (Remittances)	उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत टी.सी.एस को 5% से घटाकर 2% किया गया 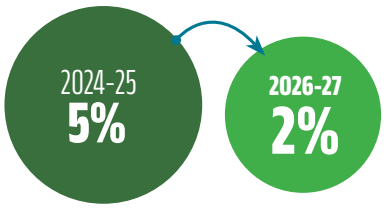	परिवारों को पहले से अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए लागत कम हो जाएगी
अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा संपत्ति की बिक्री	टी.डी.एस का भुगतान अब टैन (TAN) के बजाय पैन (PAN) का उपयोग करके किया जा सकता है	एकमुश्त पंजीकरण को समाप्त करता है और अनुपालन लागत को कम करता है

विवाद से विश्वास 2.0
टैक्स को बनाया गया कम तनावपूर्ण

करदाताओं के लिए क्या बदल रहा है?

नया कर कानून:
1 अप्रैल 2026 से स्पष्ट, सरल आयकर अधिनियम

अधकि समय:
मामूली शुल्क के साथ रिटर्न संशोधन विंडो को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किया गया

कम भागदौड़:
गैर-ऑडिट व्यवसायों और ट्रस्टों के लिए 31 अगस्त तक विस्तार के साथ आईटीआर (ITR) की समयसीमा को चरणबद्ध किया गया

प्रभाव: कम विवाद, आसान अनुपालन, अधिक भरोसा |

निवेश सीमा में वृद्धि
भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (PROI) के लिए उच्च निवेश सीमा (10% व्यक्तिगत, 24% कुल)

प्रभाव: बाजार में अधिक स्थिरता और भारत के विकास में व्यापक भागीदारी

एक आदेश प्रणाली
संयुक्त आदेश: मूल्यांकन और जुर्माना एक साथ जारी किया जाएगा, बाद में कोई अलग नोटिस नहीं

प्रभाव: एकल निर्णय और तेज़, तनाव मुक्त समाधान

अपील राहत
ब्याज पर रोक : केवल 10% मूल कर जमा के साथ अपील दायर होने पर जुर्माना ब्याज रुक जाता है

प्रभाव: कम अग्रिम बोझ और बकाया राशि में अत्यधिक वृद्धि नहीं

अपडेटेड रिटर्न विकल्प
जांच के बाद सुधार: जांच के बाद कर और 10% अतिरिक्त भुगतान करके अपडेटेड रिटर्न की अनुमति

प्रभाव: त्वरित सुधार और विवाद का जल्द समाधान

निपटान उन्मुक्ति
दोगुना कर भुगतान: दंड और अभियोजन से बचने के लिए गलत रिपोर्टिंग पर दोगुना कर का भुगतान करें

प्रभाव: स्पष्ट निपटान और कानूनी निश्चितता

छोटी चूक से सुरक्षा
गैर-अपराधीकरण: तकनीकी रिकॉर्ड और वस्तु के रूप में (in-kind) टी.डी.एस त्रुटियों पर मुकदमा नहीं चलेगा

प्रभाव: छोटी गलतियों पर केवल जुर्माना लगेगा, आपराधिक मामले नहीं

प्रथम अपराध राहत
सजा में कमी: पहले अपराध के लिए जेल की सजा 2 साल तक सीमित, जिसे अक्सर जुर्माने से बदला जा सकता है

प्रभाव: अधिक आनुपातिक और कम कठोर परिणाम

> **भारत का मिडिल क्लास उम्मीदों का पावरहाउस है**

स्वास्थ्य सेवा जो तनाव, लागत और अनिश्चितता को कम करती है

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच

रांची और तेज़पुर में नया निमहंस-2 (NIMHANS-2) और उन्नत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

प्रभाव: विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में मरीजों के करीब उन्नत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल लाता है

जीवन रक्षक दवाओं की कम लागत

कैंसर दवाओं सहित 17 आवश्यक दवाओं पर शून्य सीमा शुल्क

प्रभाव: पहले से ही उच्च चिकित्सा खर्चों का सामना कर रहे परिवारों के लिए उपचार की लागत कम करता है

दुर्लभ बीमारी के मरीजों के लिए सहायता

7 और दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं और विशेष पोषण (FSMP) का शुल्क मुक्त आयात

प्रभाव: विशिष्ट, अक्सर आयातित उपचारों को अधिक किफायती और सुलभ बनाता है

नागरिकों और परिवारों के लिए क्या बदलाव होंगे?

लघु विदेशी खुलासों के लिए राहत

अनजाने में विदेशी संपत्ति या आय के गैर-खुलासे को सुधारने के लिए एकमुश्त 6 महीने की विंडो

प्रभाव: दंड और अभियोजन से मुक्ति के साथ निष्पक्ष, श्रेणीबद्ध निपटान

सस्ता व्यक्तिगत आयात

व्यक्तिगत उपयोग के आयात पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर आधा (10%) कर दिया गया

प्रभाव: मध्यम वर्ग के लिए वैश्विक बाजार और ब्रांडों को सुलभ बनाता है

परेशानी मुक्त अंतरराष्ट्रीय यात्रा

उच्च शुल्क-मुक्त भत्ते और स्पष्ट बैगेज नियम

प्रभाव: दंड का सामना करने के बजाय भुगतान द्वारा मुद्दों को निपटाने का विकल्प, विवादों को कम करता है

वेतनभोगी और छोटे करदाताओं के लिए तेज़ टी.डी.एस राहत,

कर अधिकारियों के पास जाए बिना, नियम-आधारित स्वचालित प्रणाली के माध्यम से कम या शून्य टी.डी.एस प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे

प्रभाव: समय बचाता है, विवेकाधिकार हटाता है, और अनुमानित आय वाले छोटे करदाताओं के लिए तेज़ नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है

अब तक की यात्रा:
मध्यम वर्ग के लिए राहत

मध्यम वर्ग के लिए GST बचत उत्सव

छोटी कारें और दुपहिया वाहन (≤350cc)

जी.एस.टी.	सेस
28% → 18%	0%

दवाइयां और स्वास्थ्य बीमा

जी.एस.टी.: 0-5%

स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च कम हुआ

दैनिक घरेलू जरूरतें

साबुन, टूथपेस्ट, दूध, पनीर और स्नैक्स आदि

जी.एस.टी. 5%

शिक्षा की लागत कम करने के लिए **पेंसिल, इरेज़र और अभ्यास पुस्तिकाओं** जैसी आवश्यक शिक्षण सामग्री **को जी.एस.टी.-मुक्त** किया गया

प्रभाव

- जी.एस.टी. युक्तिकरण मध्यम वर्ग के लिए जीवन यापन की लागत को कम करता है, खर्च योग्य आय बढ़ाता है, और परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और दैनिक उपभोग में वित्तीय दबाव को कम करता है

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी-पी.एम.जे.ए.वाई)

बजटीय आवंटन	लाभार्थी
₹ 9,500 करोड़	43 करोड़

- निचली 40% आबादी को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर।

प्रभाव

42.98 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए

33,158 अस्पताल देशभर में सूचीबद्ध

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

- 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित 50% पेंशन

प्रभाव

1.22 लाख कर्मचारी (नए, सेवारत और सेवानिवृत्त) UPS चुन चुके हैं (30 नवंबर, 2025 तक)

"मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना भारत के भविष्य की कुंजी है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

बजटीय आवंटन ₹22,000 करोड़

1 करोड़
सौर रूफटॉप परिवार
वित्त वर्ष 2026-27 तक

प्रगति

21.58 लाख	27.03 लाख
इंस्टॉलेशन	घर

स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हॉउसिंग (SWAMIH)

बजटीय आवंटन: ₹650 करोड़

लक्ष्य

1 लाख+	4 लाख+
घर	लोग

प्रभाव

- **145** आवासीय परियोजनाएं | **30** शहर
- **61,000** घर वितरित | **7,000+** EWS इकाइयां
- **36,000** रोजगार सृजित | **3,500** स्थायी नौकरियां
- **~ 50%** निकाली गई पूंजी निवेशकों को लौटाई गई
- **₹6,900 Crore+** केंद्र और राज्य को राजस्व
- **₹15,531 Crore** जुटाए गए रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

बजटीय आवंटन
₹21,625.05 करोड़

₹ 2.5 लाख
EWS, LIG (निम्न आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) परिवारों को ₹2.5 लाख की सहायता।

5206
शहर और कस्बे कवर किए गए

1.14
घर निर्मित

34
MoAs हस्ताक्षर

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)

लक्ष्य
25 करोड़
निजी क्षेत्र के नागरिक पांच वर्षों में NPS के अंतर्गत

प्रभाव

- **9 करोड़+** ग्राहक
- **30 Tier-II/III शहर** कवर किए गए
- **100 शहरों** में विस्तार की योजना

प्रबंधित कुल संपत्ति (अटल पेंशन योजना के साथ)
₹ 16 लाख करोड़

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MFS)
चयनित योजनाओं में बेहतर दीर्घकालिक लाभ के लिए MFS के अंतर्गत **100% तक इक्विटी निवेश** की सुविधा

उड़े देश का आम नागरिक

बजटीय आवंटन
₹550 करोड़

सामान्य नागरिकों के लिए किफायती और सुलभ क्षेत्रीय हवाई यात्रा

1.56 करोड़+ यात्री

3.23 लाख उड़ानें

प्रभाव

- **649** मार्ग संचालित
- **93** हवाई पट्टी जोड़े गए हैं
- **12** हवाई पट्टी उत्तर-पूर्व में

₹4,300 करोड़
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण क्षेत्रीय मार्गों के लिए

अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप अब **नेशनल एविएशन नेटवर्क** का हिस्सा हैं।

अगले चरण के लक्ष्य

120 नए गंतव्य

4 करोड़ यात्री 10 वर्षों में

डिजी यात्रा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी और ड्रोन पी.एल.आई. स्कीम जैसी पहलों से एविएशन सेक्टर में **77 लाख** नौकरियां उत्पन्न हुईं

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

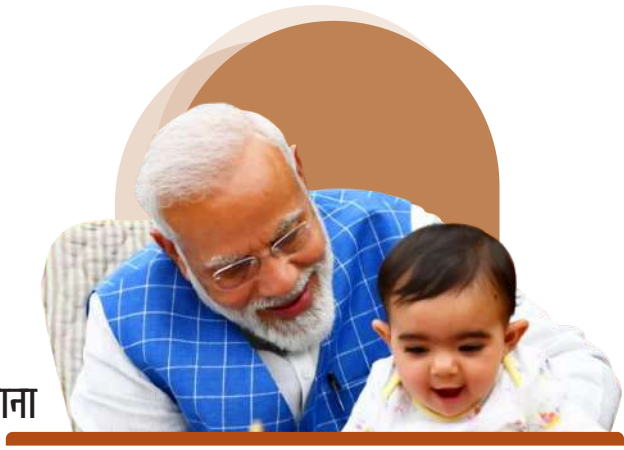

प्रभाव

समर्पित बचत खाते के माध्यम से **बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा** सुनिश्चित करना।

4.2 करोड़+
खाते खोले गए देशभर में लड़कियों के लिए, जो सालाना 8.2% की उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

वित्तीय सुरक्षा के लिए कम लागत वाला दुर्घटना बीमा

51.06 करोड़+ नामांकन

₹ 3,121.02 करोड़ का भुगतान

1,57,155 क्लेम का निपटारा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 1 वर्ष का नवीकरणीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर

23.63 करोड़+ नामांकन

₹ 18,397.92 करोड़ का क्लेमं में भुगतान

भारत के रोजगार को सुदृढ़ करने की पहल

रोजगार मेला: युवाओं को निजी क्षेत्र के रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के नेतृत्व में भर्ती अभियान

प्रभाव

16 महीनों में **11+ लाख** उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिला

विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को **61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र** जारी किए गए

स्टार्टअप्स में वृद्धि

यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स:

4 (2013) → **30x** वृद्धि → **118** (2025)

1.97 लाख DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स

स्टार्टअप्स के माध्यम से **17 लाख+** नौकरियां सृजित

बोझ कम करना, महत्वाकांक्षाओं को सशक्त बनाना

Dolphin Public School

गरीब कल्याण

समावेशी कल्याण पिछले एक दशक में सरकार की विकास नीति का प्रमुख केंद्र रहा है। सुदृढ़ **रोजगार व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान** देते हुए ग्रामीण रोजगार ढांचे के सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** जैसी पहलों ने कमजोर वर्गों के लिए आय की स्थिरता और समय पर सहायता सुनिश्चित की है।

इन प्रयासों को पोर्टेबिलिटी, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को प्राथमिकता देने वाले सुधारों से और मजबूती मिली है। वन नेशन वन राशन कार्ड, **ई-श्रम पंजीकरण, पीएम स्वनिधि** और **आयुष्मान भारत** जैसी योजनाओं ने **प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को समर्थन** देते हुए बहिष्करण को कम किया है तथा परिवारों को स्वास्थ्य एवं वित्तीय जोखिमों से संरक्षण प्रदान किया है।

- वीबी-जी राम जी
- विकसित भारत रोजगार योजना
- वन नेशन वन राशन
- आयुष्मान भारत

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में गरीबों के लिए नए प्रावधान

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल प्रशिक्षण

कौशल विकास और उत्पादन के लिए सुव्यवस्थित सहायता के माध्यम से **खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों** को मजबूत करेगी

प्रभाव

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पहल के तहत **स्थानीय कारीगरों और ग्राम उद्योगों को समर्थन** देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना

आपातकालीन एवं ट्रॉमा देखभाल योजना:

जिला अस्पतालों की क्षमता में **50% की वृद्धि** करते हुए आपातकालीन और **ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना** की जाएगी

प्रभाव

"गोल्डन आवर" के दौरान प्रारंभिक देखभाल तक शीघ्र पहुँच से जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि

गरीबों को अपने पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, जिससे वो **कर्ज़ के जाल में फँसने से बच पाएंगे**

आत्मनिर्भर भारत में जन भागीदारी

अब तक की यात्रा:
गरीबों का उत्थान

रोज़गार बने पहचान, मज़बूत हो भारत की उड़ान

वीबी- जी राम जी के लिए बजटीय आवंटन:

₹ 95,692.3 करोड़

तुलनात्मक विश्लेषण

मनरेगा

- मज़दूरों को प्रति वर्ष **100 दिनों** के रोज़गार की गारंटी देता था
- मजदूरी भुगतान में **15 दिन** तक का समय लगता था
- **कृषि कार्यों के व्यस्त सीजन** के दौरान सहायता का अभाव था
- मुख्य रूप से **मिट्टी के काम** और **गाद निकालने** जैसे कार्यों के माध्यम से रोजगार सृजन पर केंद्रित

वीबी-जी राम जी

- रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर **125 दिन** करता है
- साप्ताहिक मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करता है, जो **मनरेगा से तेज** है
- बुवाई और कटाई के व्यस्त समय के दौरान **60 दिनों** का कृषि अवकाश प्रदान करता है
- ग्रामीण परिवारों की सुनिश्चित वार्षिक आय में लगभग **25% की वृद्धि** करता है
- रोजगार को **सिंचाई प्रणाली** और **ग्रामीण बुनियादी ढांचे** जैसी संपत्ति निर्माण से जोड़ता है

समावेशी सहायता के माध्यम से गरीबों का सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY)

बजटीय आवंटन: ₹ 2,27,429 करोड़

लाभार्थी: 80 करोड़ लोग

- गरीबों को **प्रति माह 5 किलो** मुफ्त खाद्यान्न
- **₹ 11.80 लाख करोड़** का वित्तीय परिव्यय (2024-2029)

प्रभाव

- 9 वर्षों में **24.82 करोड़** भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले

पावर्टी हेडकॉउंट रेश्यो

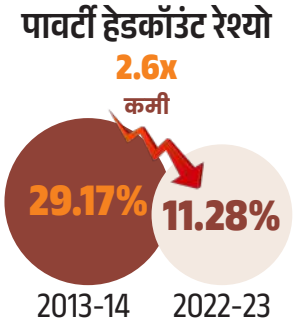

2.6x कमी

2013-14	2022-23
29.17%	11.28%

प्रधानमंत्री जन धन योजना

- **31.98 करोड़** महिलाओं सहित **57.37 करोड़** लोग
- लाभार्थी खातों में **₹ 2.83 लाख करोड़** की कुल शेष राशि
- **13.55 लाख** 'बैंक मित्रों' ने देश भर में शाखा रहित बैंकिंग सक्षम की
- **39.59 करोड़** रुपे (RuPay) कार्ड मुफ्त जारी किए गए

प्रभाव

बिचौलियों को खत्म करते हुए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण (DBT) को सक्षम बनाया

वन नेशन वन राशन कार्ड

लाभार्थी: 81 करोड़

- **191 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन** (अंतर-राज्य और राज्य के भीतर) दर्ज किए गए

प्रभाव

देशव्यापी राशन पोर्टेबिलिटी ने प्रवासी श्रमिकों को भारत में कहीं भी रियायती भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाया

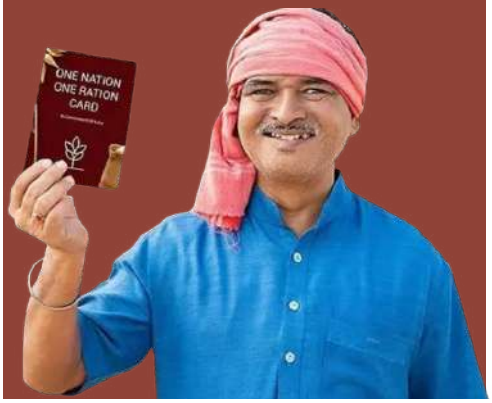

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

बजटीय आवंटन:
₹ 20,082.70 करोड़

देश में **3.5 करोड़ नौकरियां** उत्पन्न करने का लक्ष्य

विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी क्षेत्रों में **सामाजिक सुरक्षा** को मजबूत करना।

प्रभाव

रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है और रोजगार क्षमता बढ़ाता है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों का कल्याण

e-Shram पोर्टल में पंजीकृत श्रमिक:

31 करोड़ असंगठित श्रमिक

5 लाख गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक

प्रभाव

सामाजिक सुरक्षा संहिता ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक पहचान दी

भविष्य की पेंशन योजनाओं के लिए प्रावधान सक्षम किए

PM SVANidhi

PM SVANIDHI

बजटीय आवंटन:
₹ 900 करोड़

लाभार्थी: 71.48 लाख

स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद मिली

वितरित ऋण:
1.05 करोड़

कुल वितरित राशि:
₹ 16,128 करोड़

प्रभाव

69% लाभार्थी एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी समुदायों से हैं

जल जीवन मिशन
(हर घर जल)

बजटीय आवंटन: ₹ 67,670 करोड़
लाभार्थी: ₹15.8 करोड़ ग्रामीण परिवार

नल कनेक्शन

3.23 करोड़ (2019) → 5x वृद्धि → 15.7 करोड़ (2025)

घरेलू कवरेज

17% (2019) → 5x वृद्धि → 81% (2025)

प्रभाव

- महिलाओं द्वारा पानी इकट्ठा करने के समय में प्रतिदिन **5.5 करोड़ घंटे** की कमी
- **3 करोड़ श्रम-वर्ष** के रोजगार सृजन की क्षमता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

बजटीय आवंटन:
₹ 250 करोड़
लाभार्थी: **46.92 लाख**

- **60 वर्ष** की आयु के बाद **₹ 3000 प्रति माह** की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन
- लाभार्थी की मृत्यु पर, जीवनसाथी **50% पेंशन** का हकदार

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

19% (2015) → 3x वृद्धि → 64.3% (2025)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण 2.0)

बजटीय आवंटन: ₹ 7,192 करोड़

- **12.03 करोड़** शौचालयों का निर्माण
- **5.8 लाख** गांव 'स्वच्छ भारत मिशन' गांव के रूप में मान्य
- **5.6 लाख** गांव 'ओ.डी.एफ प्लस' (खुले में शौच मुक्त) घोषित

प्रभाव

डेंगू मृत्यु दर

1% (2008) → 10x कमी → 0.1% (2019)

> गरीब की जीवन को आसान बनाना ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हैं

आयुष्मान भारत

(प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)

बजटीय आवंटन: **₹ 9,500 करोड़**

लाभार्थी: **43 करोड़**

12 करोड़ कमजोर परिवारों को **₹ 5 लाख** का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा

10.07 करोड़ अधिकृत अस्पताल में भर्ती

86 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक नामांकित

33,128 पैनलबद्ध अस्पताल **(15,619 निजी अस्पताल)**

प्रभाव

- हर साल **6 करोड़** से अधिक भारतीयों को स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी में गिरने से बचाया

Atal Pension Yojana

अटल पेंशन योजना

बजटीय आवंटन: ₹ 547.8 करोड़

- 18-40 वर्ष के नागरिकों के लिए
- नामांकन 8.34 करोड़ के पार (48% महिलाएं)

प्रभाव

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन कवरेज प्रदान करता है

प्रधानमंत्री आवास योजना

बजटीय आवंटन: **₹ 54,916.7 करोड़**

लाभार्थी: **4 करोड़**

3 करोड़ घरों का निर्माण

प्रभाव

पिछले 9 वर्षों में **585 करोड़** से अधिक श्रम-दिवस सृजित किए

युवा

कई दशकों तक भारत के युवाओं में प्रतिभा और आकांक्षाएँ होते हुए भी **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रासंगिक कौशल और सार्थक अवसरों** तक सीमित पहुँच के कारण वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। प्रशिक्षण व्यवस्था और संस्थागत सहयोग में संरचनात्मक कमियों के चलते अनेक युवा **देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति** में सक्रिय भागीदारी से वंचित रह गए, जबकि उनमें योगदान देने की प्रबल इच्छा थी।

वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में **युवाओं को विकास के केंद्र में रखा गया**। शिक्षा सुधार, कौशल विकास, उद्यमिता और खेलों पर निरंतर ध्यान के माध्यम से पिछले एक दशक में अध्ययन, रोजगार और नेतृत्व के नए अवसर सृजित हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित इन प्रयासों ने युवाओं को सशक्त बनाते हुए, **आत्मनिर्भर भारत के निर्माण** में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है।

- मेरा युवा भारत
- खेलो इंडिया
- स्टार्टअप इंडिया
- पीएम सेतु

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन (₹ करोड़ में)

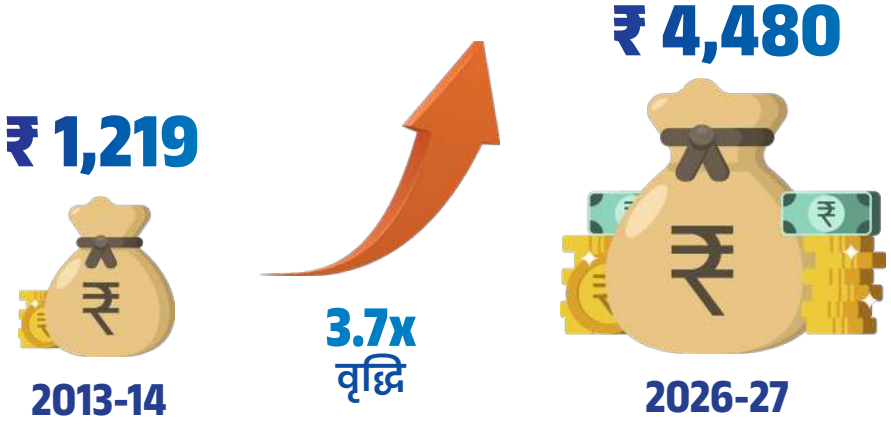

केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधान

अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के लिए विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए **क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों** की स्थापना

प्रभाव

- मांग वाले अंतर्देशीय कार्गो क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रोजगार और **विशेष कौशल विकास के अवसर** प्रदान करना

ICAI, ICSI और ICMAI जैसे पेशेवर निकायों को छोटे शहरों में **'कॉर्पोरेट मित्र'** का कैडर बनाने के लिए **अल्पकालिक, मॉड्यूलर पाठ्यक्रम** पेश करने में सक्षम बनाना

प्रभाव:

- ऐसे 'पैरा-प्रोफेशनल' तैयार करना जो **MSME** (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को सहायता प्रदान कर सकें

हमारे जैसे युवा राष्ट्र को पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए

भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान युवाओं के लिए AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कौशल का **शुरुआती अनुभव प्रदान करने** के लिए 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करेगा

प्रभाव

- उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए **रचनात्मक पेशेवरों** का एक पूल तैयार करना

कुशल भारतीय डिजाइनरों की कमी को दूर करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में **एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना**

प्रभाव

- पूर्वी क्षेत्र में **डिजाइन शिक्षा** और विकास को बढ़ावा देना

पांच नियोजित विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करना, ताकि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान, कौशल और आवास को एक ही स्थान पर लाकर एकीकृत शैक्षणिक क्षेत्र बनाया जा सके

प्रभाव

- युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए **शिक्षा-उद्योग संबंधों को मजबूत करना**

खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए **चार टेलीस्कोप सुविधाएं स्थापित** की जाएंगी

प्रभाव

- इमर्सिव अनुभवों के माध्यम से **खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी को बढ़ावा देना**
- **युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित** करना

दवा क्षेत्र में R&D को मजबूत करने के लिए तीन नए **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान** संस्थान स्थापित करना

प्रभाव

- बायो फार्मा पेशेवरों का **कुशल टैलेंट पूल** बनाना
- आयातित दवाओं पर **निर्भरता कम करना**

समर्थ 2.0 के तहत संगठित कपड़ा क्षेत्र में **रोजगार देने के लिए** एक उद्योग-जुड़ा कौशल **पारिस्थितिकी तंत्र** बनाना

प्रभाव

- **प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम** तैयार करना

20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर **10,000 गाइडों** के कौशल विकास के लिए पायलट योजना

प्रभाव

- स्थानीय गाइडों की **आजीविका को बढ़ावा** देना

10 प्रमुख विषयों में **सहायक स्वास्थ्य पेशेवर संस्थान का विस्तार**

बजटीय आवंटन:
₹ 1,000 करोड़

प्रभाव

- विशेष स्वास्थ्य देखभाल सहायता कर्मचारियों की कमी को दूर करना

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे से संरेखित कार्यक्रमों के साथ **जेरियाट्रिक (वृद्धजन) देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र** का सृजन

प्रभाव

- स्वास्थ्य संस्थानों पर **बोझ कम करना**
- **1.5 लाख बहु-कौशल देखभाल कर्ताओं** को प्रशिक्षित करना

आयुष (AYUSH) क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए **तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना**

प्रभाव

- युवाओं के लिए **करियर के नए अवसर**
- आयुर्वेद उत्पादों में **उद्यमिता को बढ़ावा देना**

अब तक की यात्रा:
युवाओं के लिए अवसर

युवा देवो भवः; युवा शक्ति देवो भवः

भारत के **शिक्षा परिदृश्य में बदलाव**

विश्वविद्यालय

760 (2014) → 76% वृद्धि → 1,338 (2025)

उच्च शिक्षण संस्थान

51,534 (2014) → 36% वृद्धि → 70,018 (2025)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)

ज़ंज़ीबार और अबू धाबी में IIT के दो विदेशी परिसर स्थापित किए गए हैं

16 (2014) → 44% वृद्धि → 23 (2025)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs)

13 (2014) → 61.5% वृद्धि → 21 (2025)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)

7 (2014) → 3x वृद्धि → 20 (2025)

QS वर्ल्ड रैंकिंग के 2026 संस्करण में **54 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल**

11 (2015) → 5x वृद्धि → 46 (2025)

प्रभाव

अनुसंधान की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ वैश्विक मानकों को संस्थागत बनाया

मेडकिल कॉलेज

MBBS सीटें

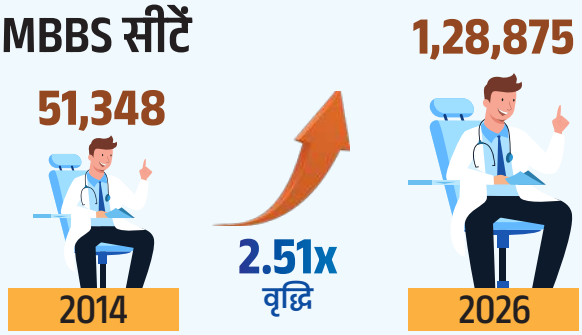

PG सीटें (मेडकिल)

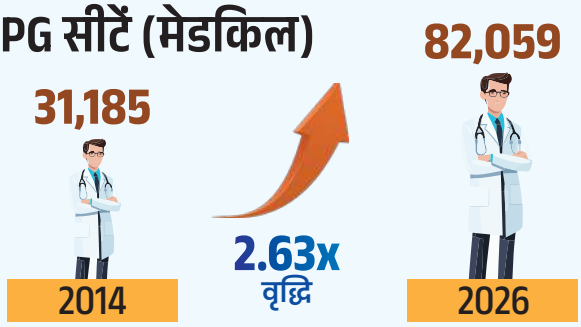

प्रभाव

मध्यम और निम्न-आय वाले छात्रों के लिए पहुंच का विस्तार

मेरा युवा भारत

बजटीय आवंटन: ₹ 655 करोड़

- **उन्नत उपकरणों** के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण मंच
- इसने **2 करोड़** से अधकि युवाओं और **1.20 लाख** संगठनों को जोड़ा है

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

बजटीय आवंटन: ₹2,800 करोड़

उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देता है और नवीन पाठ्यक्रम पेश करता है

प्रभाव

- वर्तमान में **1.6 करोड़ से अधिक लाभार्थी** नामांकित
- PMKVY के अंतर्गत **1.29 करोड़ लाभार्थी प्रमाणित**
- **1.6 करोड़ लाभार्थियों** में से **45% महिलाएं**
- PMKVY 3.0 तक **अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT)** में **प्लेसमेंट दर 42.8%**
- 24.3 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिला

प्रभाव

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से युवाओं के लिए डिजिटल अंतर को कम करना

#startupindia

फंड ऑफ फंड्स
बजटीय आवंटन: ₹ 900 करोड़

स्टार्टअप्स में वृद्धि

2,07,135

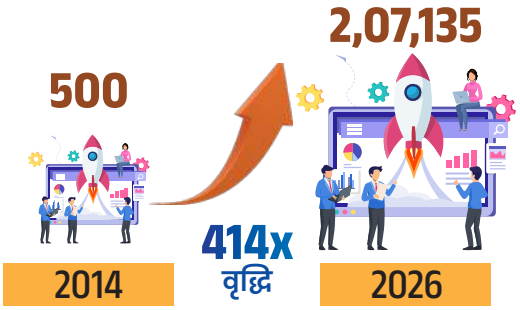

500

2014 — 414x वृद्धि — 2026

IT क्षेत्र में 21,000 और स्वास्थ्य सेवा में 17,000 स्टार्टअप्स

कृषि, शिक्षा और सेवा क्षेत्र: प्रत्येक में 11,000 स्टार्टअप्स

यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में वृद्धि

120

4

2014 — 30x वृद्धि — 2025

(कुल मूल्यांकन $350 बिलियन से अधिक के साथ)

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग

91	38
2015	2025

प्रभाव

9 वर्षों **में 17,28,000 नौकरियां पैदा हुईं**

देश के **48% स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा स्थापित** हैं

रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) योजना

उत्पादन क्षेत्र पर जोर देने के साथ रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित

लक्ष्य

₹ 99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ 2 वर्षों में 3.5 करोड़+ नौकरियां

प्रभाव

इनमें से **1.92 करोड़ लाभार्थी** पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा होंगे

> **भारतीय युवाओं को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए।**

पीएम युवा 3.0

युवा शक्ति भारत की सुधार यात्रा को **विकसितभारत@2047** की ओर ले जा रही है

- **राष्ट्रीय पुस्तक संस्कृति** को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए मेंटरशिप
- **22 आधिकारिक भाषाओं** और अंग्रेजी में **2,840 पुस्तक** प्रस्ताव प्राप्त हुए

प्रभाव

- 6 महीने के लिए **₹50,000** प्रति माह और **10% रॉयल्टी**
- 43 विजेताओं **(24 पुरुष, 19 महिलाएं)** ने **केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत** की

पीएम-सेतु

- **₹6,140.5 करोड़** का कुल बजट
- **हब-एंड-स्पोक मॉडल** का उपयोग करके **1,000 से अधिक सरकारी आईटीआई (ITI)** का आधुनिकीकरण

प्रभाव

- प्रशिक्षण को **आधुनिक नौकरी बाजार** की जरूरतों के साथ जोड़ता है

युवा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है।

नरेन्द्र मोदी

नव्या योजना

किशोरियों को आधुनिक और उभरती हुई भूमिकाओं में कौशल प्रदान करने की योजना

19 राज्यों (उत्तर-पूर्व सहित) के 27 आकांक्षी जिलों में **3,850 लड़कियों को कवर किया गया**

7 घंटे का पूरक मॉड्यूल जिसमें शामिल हैं:

- पारस्परिक कौशल
- संचार कौशल
- कार्यस्थल सुरक्षा
- वित्तीय साक्षरता

प्रभाव

जेंडर इनक्लूसिव स्किल्स का निर्माण और लड़कियों के लिए शिक्षा से आजीविका के अंतर को कम करना

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025

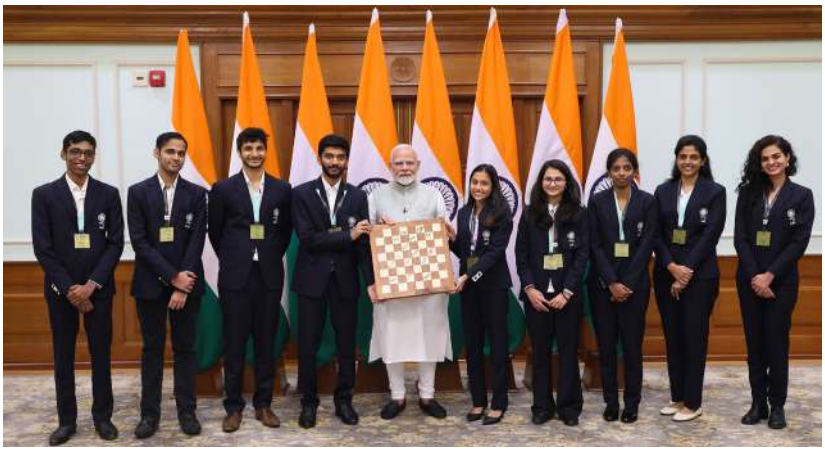

हमने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला शुरू किया है, वह अब 'रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस' बन चुका है। इसके केंद्र में हमारी युवा शक्ति ही है।

नरेन्द्र मोदी

एन.एस.जी. अधिनियम, 2025

- भारतीय ओलंपिक संघ
- राष्ट्रीय खेल संघ
- भारतीय पैरालंपिक समिति
- अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त निकाय

मुख्य विशेषताएं

सुरक्षित खेल नीति	निष्पक्ष चुनाव (राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल)	पारदर्शी शिकायत निवारण

प्रभाव

वैश्विक पारदर्शिता मानदंडों के साथ संरेखित, **महिलाओं का प्रतिनिधित्व** और वित्त पोषण सुनिश्चित करना

खेलो इंडिया

बजटीय आवंटन:₹ 924.35 करोड़

- **जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा** देने की एक सरकारी पहल
- **₹3,124.12 करोड़** की **326 नई खेल बुनियादी ढांचा** परियोजनाओं की मंजूरी

ओलंपिक पदकों में वृद्धि

पैरालंपिक पदकों में वृद्धि

एशियन गेम्स पदकों में वृद्धि

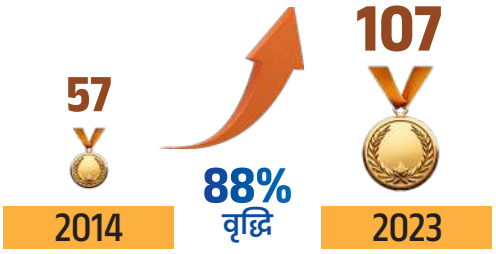

प्रभाव

- **1,045 खेलो इंडिया केंद्रों** की स्थापना
- **34 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर** ऑफ एक्सीलेंस की अधिसूचना
- **2,845 खेलो इंडिया एथलीटों** को सहायता

खेलो इंडिया चैंपियंस को तराशता है, एक फिट भारत बनाता है।

अन्नदाता

किसानों को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखते हुए पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में आय सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सुनिश्चित खरीद के साथ बढ़ा हुआ **न्यूनतम समर्थन मूल्य**, पीएम-किसान के अंतर्गत प्रत्यक्ष आय सहायता और **पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से व्यापक जोखिम कवरेज** ने कृषि परिवारों की **आर्थिक अनिश्चितता को कम किया** है।

आय सहायता से आगे बढ़ते हुए उत्पादकता, बाज़ार और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया है। **ई-नाम का एकीकरण**, दलहन उत्पादन के लिए लक्षित कार्यक्रम, उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता तथा कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने जैसी पहलों ने अवसरों का विस्तार किया है, **आयात पर निर्भरता घटाई है** और **भारत को एक खाद्य अधिशेष राष्ट्र के रूप में सुदृढ़** किया है।

- एम.एस.पी. में वृद्धि
- दालों में आत्मनिर्भरता
- ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

वित्त वर्ष **2026-27** *के*
केंद्रीय बजट *के*
प्रावधान

विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की बहुत अहम भूमिका है

नरेन्द्र मोदी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन (₹ करोड़)

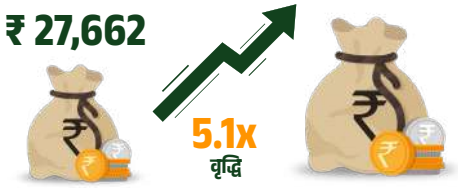

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन (₹ करोड़)

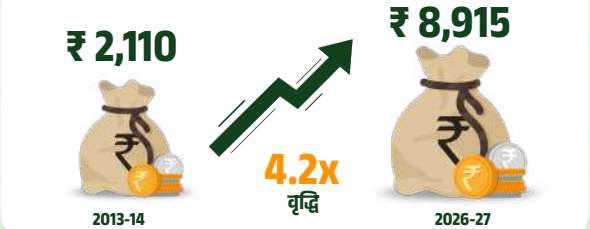

केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधान

पशुधन स्वास्थ्य और रोजगार

पशु चिकित्सा सहायता

ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी निजी पशु चिकित्सा संस्थानों को समर्थन देगी ताकि पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या **20,000** से अधिक बढ़ाई जा सके

प्रभाव रोग निगरानी में सुधार, महामारी के जोखिम में कमी, और **डेयरी, चमड़ा और मांस की गुणवत्ता** में वृद्धि

उद्यमिता विकास

क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी पशुपालन क्षेत्र का समर्थन करेगी और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी (PERI-URBAN) रोजगार पैदा करेगी

प्रभाव **डेयरी गुणवत्ता** में सुधार, खाद्य मानकों में सुधार और किसानों को **वैश्विक उत्पादकता बेंचमार्क** तक पहुंचने में मदद करना

समुद्री कृषि के लिए समर्पित कार्यक्रम

मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण

स्टार्ट-अप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOS) को समर्थन, साथ ही **500 जलाशयों** और अमृत सरोवरों का विकास

प्रभाव: छोटे मछुआरों की आय बढ़ाता है, बाजार पहुंच में सुधार करता है और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और हाई सीज (HIGH SEAS) में समर्थन

विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछली को **शुल्क -मुक्त निर्यात व्यवस्था** प्राप्त होगी

प्रभाव: लाभप्रदता को बढ़ाता है, **तटीय आजीविका का समर्थन** करता है और पलायन को कम करता है

समुद्री भोजन

सीफूड प्रोसेसिंग इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात सीमा निर्यात टर्नओवर के 1% से बढ़कर 3% हो जाएगी

प्रभाव: लागत कम करता है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है और टिकाऊ तटीय आजीविका का समर्थन करता है

उच्च मूल्य वाली कृषि का समर्थन

बजटीय आवंटन:
₹ 350 करोड़

नारियल, काजू, कोको, चंदन, अखरोट बादाम और पाइन नट्स (चिलगोज़ा) जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का कायाकल्प, बेहतर रोपण सामग्री और प्रसंस्करण के माध्यम से समर्थित किया जाएगा

प्रभाव: उत्पादन में विविधता लाता है, आय बढ़ाता है, आयात निर्भरता कम करता है, और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांड बनाता है

किसानों का कल्याण
राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है

खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार

बजटीय आवंटन:
₹ 150 करोड़

BHARAT-VISTAAR

एग्रीकल्चर स्टैक और ICAR प्रथाओं को एकीकृत करने वाला एक **बहुभाषी ए.आई. प्लेटफॉर्म उत्पादकता में सुधार** और जोखिम कम करने के लिए अनुकूलित सुझाव प्रदान करेगा

प्रभाव: किसान सहायता प्रणालियों को मजबूत करता है और **जलवायु परिवर्तन** तथा कीटों के प्रकोप के प्रति लचीलापन बढ़ाता है

सहकारी समितियों के लिए कर कटौती

कटौती का विस्तार

प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कर कटौती में अब **पशु आहार** और बिनौला (COTTON SEED) शामिल हैं, साथ ही अंतर-सहकारी लाभांश कटौती योग्य रहेंगे

अधिसूचित **राष्ट्रीय सहकारी महासंघों** की निवेश से प्राप्त लाभांश आय 31 जनवरी 2026 तक सदस्यों को वितरित किए जाने पर **3 वर्षों के लिए कर-मुक्त** होगी

प्रभाव: थोक उत्पादन और **कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं** को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण उत्पादकों को लाभ होता है

“हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है

अब तक की यात्रा:
किसानों की समृद्धि

अन्नदाता को सशक्त बनाना
विकसितभारत@2047

कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ करना

खाद्यान्न
264.4 MT → 357.7 MT
35.3%
2013-14 → 2024-25

दूध
146.3 MT → 247.8 MT
69.4%
2014-15 → 2024-25

दलहन
19.26 MT → 25.23 MT
31%
2013-14 → 2024-25

मांस
6.69 MT → 10.50 MT
56.9%
2014-15 → 2024-25

दुधारू पशु
85.66 M → 111.76 M
30.5%
2014-15 → 2023-24

मछली
9.57 MT → 19.75 MT
2x
2013-14 → 2024-25

एम.एस.पी में बढ़त

लागत के 1.5 गुना पर गारंटीकृत खरीद, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है

धान (खरीफ)
₹ 1,310 प्रति क्विंटल (2013-14) → ₹ 2,369 प्रति क्विंटल (2025-26)
81% वृद्धि

गेहूं (रबी)
₹ 1,350 प्रति क्विंटल (2013-14) → ₹ 2,425 प्रति क्विंटल (2025-26)
80% वृद्धि

अन्नदाता केवल किसान नहीं, भारत की आत्मा हैं

बजटीय आवंटन
₹ 63,500 करोड़

पीएम - किसान

लाभार्थी: 11 करोड़

₹ 4.09 लाख करोड़
वितरित राशि

₹ 6,000
वार्षिक वित्तीय सहायता

21
किस्तें

प्रभाव और लाभ

ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग

₹ 1,430 (2011-12) → 3x वृद्धि → ₹ 4,122 (2023-24)

85%
किसानों ने उच्च आय की सूचना दी

25%
लाभार्थी महिला किसान हैं

बजटीय आवंटन
₹ 12,200 करोड़

पीएम - फसल बीमा योजना

लाभार्थी:
22.7 करोड़ कृषि
निस्तारित क्लेम राशि:
₹1.8 लाख करोड़

3.2 करोड़ (2022-23) → 32% वृद्धि → 4.2 करोड़ (2024-25) नामांकित किसान

78.4 करोड़ बीमित आवेदन

15.1 करोड़ किसान आवेदनों का कवरेज

पीएम धन धान्य कृषि योजना

100
कम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को लक्षित किया गया

1.7 करोड़
किसान लाभान्वित होंगे

20-30%
फसल की पैदावार में अपेक्षित वृद्धि

₹ 24,000 करोड़
छह वर्षों के लिए वार्षिक परिव्यय

कृषि निर्यात

भारत एक खाद्य - अधिशेष देश बन गया है और दुनिया भर में पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है

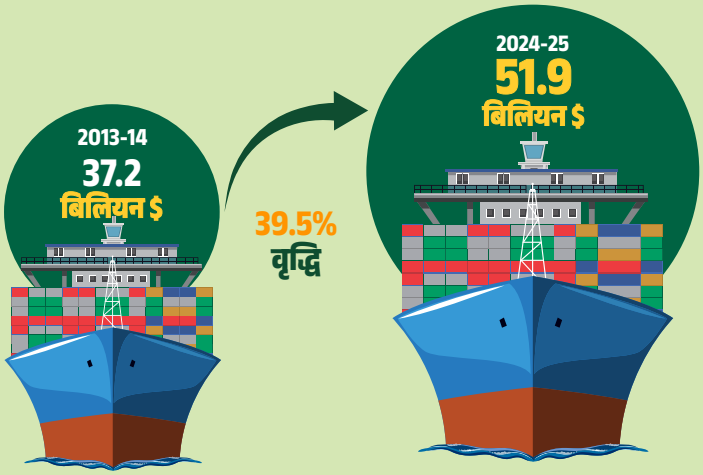

बासमती चावल का निर्यात

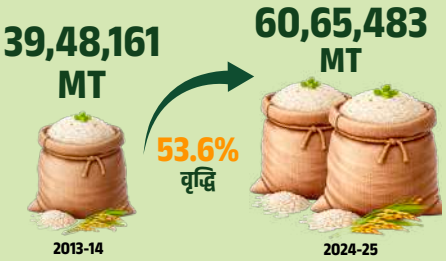

समुद्री उत्पादों का निर्यात

कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य

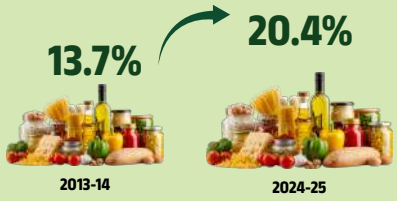

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट

1522 एकीकृत मंडियां

247
कुल व्यापार योग्य कृषि उत्पाद

2,71,157
व्यापारी E-NAM प्लेटफॉर्म पर नामांकित

₹ 4.39
लाख करोड़ मूल्य का कृषि उत्पाद व्यापार

1,79,83,156
किसान E-NAM प्लेटफॉर्म पर नामांकित

किसान की उन्नति ही देश की प्रगति है

नरेन्द्र मोदी

किसानों को उर्वरक की पहुंच सुनिश्चित करना

सब्सिडी बजट

₹ 65,971.5 करोड़

2013-14

2.6x वृद्धि

₹ 1,70,799 करोड़

2026-27

उर्वरकों का घरेलू उत्पादन

433.3 लाख टन

2021

21.1% वृद्धि

524.6 लाख टन

2025

प्रभाव

आयात पर निर्भरता कम हुई क्योंकि **73%** उर्वरक आवश्यकताएं घरेलू स्तर पर पूरी की गईं

दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन

घरेलू दलहन उत्पादन को **350 लाख टन** तक बढ़ाने का लक्ष्य

बजटीय परिव्यय (2025-26 से 2030-31) **₹ 11,440 करोड़**

खेती के क्षेत्र को **2030-31** तक **310 लाख हेक्टेयर** तक विस्तारित करना

लगभग **2 करोड़ किसानों** को लाभ होगा

प्रभाव

4 वर्षों तक एम.एस.पी पर तूर, उड़द और मसूर की **100% खरीद**

विशेष रूप से दलहन के लिए **35 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र जोड़ना

> **किसान ही अन्नदाता है, वही देश का भाग्यविधाता है**

नारी

लंबे समय तक महिलाओं की प्रगति वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और **सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व** की सीमाओं से बाधित रही। परिवार और समाज में केंद्रीय भूमिका निभाने के बावजूद अनेक **महिलाएँ आर्थिक अवसरों और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहीं**, जिससे उनके समग्र कल्याण और दीर्घकालिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा।

पिछले एक दशक में महिलाओं को शासन और विकास के केंद्र में रखते हुए इस स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**, **पीएम उज्ज्वला योजना**, **मिशन शक्ति** तथा लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के विस्तार जैसी पहलों से **महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण** और नेतृत्व क्षमता को मजबूती मिली है। ये प्रयास महिला-नेतृत्वित विकास की दिशा में स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं, जहाँ **नारी शक्ति को एक सशक्त और समावेशी भारत की आधारशिला** माना गया है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- लखपति दीदी
- वित्तीय सशक्तिकरण
- महिला सुरक्षा और संरक्षण

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रावधान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन

38%

₹ 20,440 करोड़
2013-14

₹28,183 करोड़
2026-27

2026-27 के केंद्रीय बजट से प्रावधान

छात्राओं के लिए छात्रावास

प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) संस्थानों में

- **STEM** क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश को आसान बनाता है
- **अर्थव्यवस्था के उच्च-उत्पादकता** वाले क्षेत्रों में महिलाओं की **भागीदारी को मजबूत** करता है
- **घर से दूर** रहने वाली महिलाओं की **सुरक्षा सुनिश्चित** करता है

क्रेडिट-लिंक्ड सपोर्ट

मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्यमों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सपोर्ट

- महिला किसानों को मत्स्य पालन मूल्य **श्रृंखला में एक प्रमुख सहभागी** बनाता है
- महिलाओं के नेतृत्व वाले मत्स्य उद्यमों के लिए **संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार** करता है

स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट्स

क्लस्टर-स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट्स के रूप में

- महिलाओं में **वित्तीय स्वायत्तता** को प्रोत्साहित करता है
- **महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों** के लिए बाजार तक पहुंच का विस्तार करता है
- **मूल्य प्राप्ति** और **उद्यम** की व्यवहार्यता में सुधार करता है

सशक्त नारी, सक्षम नारी

अब तक की यात्रा:
नारी को सम्मान

नारी शक्ति
देश की
शक्ति

भारत की सफलता की कहानी

के केंद्र में महिलाएं

महिला नेतृत्व वाले एम.एस.एम.ई दोगुने हुए

2010-11 में 1 करोड़ से बढ़कर
2023-24 में
1.92 करोड़

DPIIT के पंजीकृत

स्टार्टअप्स में से लगभग 50%

में कम से कम **एक महिला निदेशक** है

महिला **श्रम बल** भागीदारी अनुपात

23.3% 2017-18

41.7% 2023-24

वर्ष 2024-25 के दौरान
26.9 लाख महिला सदस्य
ई.पी.एफ.ओ से जुड़ी

पीएम-मुद्रा योजना की
68% लाभार्थी महिलाएं हैं

पीएम-मुद्रा
वितरण में 13% CAGR की वृद्धि, जो
₹ 62,679
प्रति महिला तक पहुँच गई

28 लाख
से ज़्यादा **महिला-स्वामित्व वाले एम.एस.एम.ई** को सुविधा प्रदान की गई

लिंग अनुपात

943 2010-11

1020 2023-24

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

बजटीय आवंटन:
₹2,573 करोड़
मिशन शक्ति के तहत

लाभार्थी
4.67 करोड़

प्रभाव

प्रसव पूर्व जांच कराने वाली माताएं

2021 **70%**
2016 58.6%

संस्थागत प्रसव

2021 **61.9%**
2016 52.1%

टीकाकरण वाले बच्चे

2021 **76.4%**
2016 62%

मातृ मृत्यु दर

2014-16 130
2018-20 **97**

शिशु मृत्यु दर
(प्रति हजार जीवित जन्म)

2016 40.7%
2021 **35.2%**

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं कार्यस्थल सुरक्षा के लिए पहलें

411
शक्ति सदन (कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास)

531
सखी निवास देश भर में कार्यात्मक

1.30 lakh
लाख कार्यस्थल शी-बॉक्स पोर्टल में पंजीकृत

93.48 लाख
महिलाओं को सहायता हेल्पलाइन के द्वारा

वन स्टॉप सेंटर
1025
स्वीकृत
865
संचालित

प्रभाव
12.67 लाख महिलाओं को सहायता

POSH जागरूकता और अनुपालन में सुधार, प्रकटीकरण को बढ़ावा

भारत के शीर्ष 30 कंपनियों में

902
शिकायतें दर्ज की गईं

88%
शिकायतों का निपटारा हुआ

पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY)

उज्ज्वला ने **धुएं को मुस्कान से बदल दिया है**

बजटीय आवंटन: ₹11,084

लाभार्थी : 10.41 करोड़

वार्षिक प्रति व्यक्ति एल.पी.जी खपत:

3.01 वित्त वर्ष 2019-20 → **4.43** वित्त वर्ष 2024-25

पीएम उज्ज्वला योजना से अनुमानित **₹6.46 लाख करोड़** का कल्याणकारी लाभ उत्पन्न हुआ

प्रति वर्ष **1.5 लाख** जीवन बचाए गए

श्वसन रोगों एवं बीमारियों में **उल्लेखनीय कमी** आई है

बायोफ्यूल और लकड़ी का उपयोग कम करके **पर्यावरण वहनीयता में सुधार**

निष्पक्षता और चुनावी प्रतिनिधित्व के माध्यम से परिवर्तन

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए **33% सीटें** आरक्षित की गईं

2.75 करोड़ **पीएम आवास-ग्रामीण** लाभार्थियों में से **लगभग 73% महिलाएं** हैं

लखपति दीदी योजना

लाभार्थी : 1.48 करोड़

755 जिलों में फैले **7182 ब्लॉक** शामिल किए गए

स्वयं सहायता समूह
91,95,675

मास्टर ट्रेनर
6,611

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
6,611

प्रभाव

वित्तीय सशक्तिकरण

महिलाएं अब सालाना ₹1 लाख या उससे ज़्यादा कमा रही हैं

उद्यमिता विकास

90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, जिनमें **9-10 करोड़ महिलाएं शामिल** हैं, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों का विस्तार कर रही हैं

प्रभाव

वंचित समूहों को विस्तारित पोषण सहायता

बच्चों में बौनापन में कमी

2016 38.4%

2021 **35.5%**

बच्चों में कुपोषण की दर में कमी

2016 21%

2021 **19.3%**

कम वजन वाले बच्चो में कमी

2016 35.7%

2021 **32.1%**

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

बजटीय आवंटन: 23,100 करोड़

लाभार्थी : 8.86 करोड़

02 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों (AWCS) को **सक्षम आंगनबाड़ी** के रूप में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गई

14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र जोड़े गए

875 आंगनबाड़ी केंद्र, जिनसे **27,785 जनजातीय** लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

16,000 से अधिक कार्यात्मक जनऔषधि केंद्र

96.30 करोड़ सुविधा सैनिटरी नैपकिन की संचयी बिक्री

₹1 प्रति पैड ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल **'सुविधा'** सैनिटरी नैपकिन का मूल्य

स्वच्छ तरीकों का उपयोग करने वाली महिलाओं (15-24 वर्ष) का **प्रतिशत बढ़ा**

2016 57.6%

2021 **77.3%**

> **हमारा ध्यान भारत की प्रत्येक बेटी के लिए गरिमापूर्ण जीवन और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर है**

हमारे बारे में

कानून, नीति और शासन केंद्र (CLPG), NFPRC फाउंडेशन के अंतर्गत स्थापित एक विशेषीकृत केंद्र है। CLPG एकीकृत कानूनी एवं नीति अनुसंधान के माध्यम से भारत की विधायी और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

NFPRC दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए व्यापक, सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान करता है, साथ ही नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहयोग हेतु त्वरित एवं प्रभावी शोध भी प्रदान करता है। अपने कार्यों के माध्यम से NFPRC सरकारों को नीतियों की समीक्षा करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने तथा शासन परिणामों की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायता करता है। इसके साथ ही यह शोध प्रकाशनों, नीति संक्षेपों और श्वेत पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय नीति विमर्श में भी योगदान देता है।

यह बजट
अपार अवसरों का एक
राजमार्ग है, जो आज के
सपनों को पूरा करता है
और भारत के उज्ज्वल
भविष्य की नींव को
मजबूत करता है।

नरेन्द्र मोदी

NATION FIRST
POLICY RESEARCH CENTRE

LinkedIn

Substack

lr@nationfirstpolicy.org | samparka@nationfirstpolicy.org | clpg@nationfirstpolicy.org